राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

रक्षामंत्री से मिल सीएम फडणवीस

रूस : सिग्नल टूटने के बाद पहाड़ पर क्रैश हुआ विमान, 49 यात्रियों की दर्दनाक मौत

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 212 | रायपुर | शुक्रवार 25 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

दिल्ली, यूपी व गुजरात में बड़े हमले की साजिश नाकाम, पकड़े गए अल-कायदा के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा

अहमदाबाद/नई दिल्ली

गुजरात एटीएस ने एक बड़े अंतर-राज्यीय ऑपरेशन में अल-कायदा के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां गुजरात, दिल्ली और नोएडा से की गई हैं। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के खिलाफ भारत में माहौल बिगाड़ने और दिल्ली, यूपी व गुजरात में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। गुजरात एटीएस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आतंकी 'अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS)' से जुड़े हैं। इनका मुख्य काम भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में एक विशेष समुदाय के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काना और रेडिकलाइज्ड करना था। जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना के 'ऑपरेशन बुनयान उल मरसूस' के समर्थन में काम कर रहा था। इन आतंकियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कई बार पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों से संपर्क साधा था।

पीएम मोदी बोले- यह साझेदारी नहीं, साझा समृद्धि का रोडमैप

भारत-यूके के बीच FTA समझौता

एजेंसी - भारत और ब्रिटेन ने आज 24 जुलाई को मुक्त व्यापार समझौते यानी एफ्टीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समझौता केवल एक आर्थिक सौदा नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा समृद्धि का रोडमैप है। भारत और ब्रिटेन इस समझौते को India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) कहा जा रहा है। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और कीर स्टार्मर ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में इस समझौते को नई वैश्विक साझेदारी का मील का पत्थर बताया।

संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन की धरती से अपने संबोधन की शुरुआत नमस्कार के साथ की और प्रधानमंत्री स्टार्मर द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत का आभार जताते हुए कहा, ÷आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। कई वर्षों की मेहनत के बाद आज संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र

आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है।÷

पीएम मोदी ने साफ किया कि इस समझौते से भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर, रत्न-आभूषण, सीफूड और इंजीनियरिंग उत्पादों को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा। कृषि और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खुलेंगे, जो भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSMEs के लिए फ ायदेमंद साबित होगा।

भारत के लिए क्या रहेगा लाभः भारतीय निर्यात के 99% हिस्से को यूके में ड्यूटी-फ्री एक्सेस, जिससे लगभग 23 अरब डॉलर का व्यापारिक अवसर खुलेगा।

95 प्रतिशत कृषि उत्पादों को यूके में बिना शुल्क के निर्यात की सुविधा। Double Contribution Convention पर सहमति- जिससे भारतीय सेवा क्षेत्र, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, को नई ऊर्जा मिलेगी।

Ease, Cost Confidence of Doing Business में वृद्धि।

भारतीय स्किल्ड टैलेंट को यूके में नए अवसर।

यूके में बने मेडिकल डिवाइसेज और एयरोस्पेस पार्ट्स भारत में सुलभ और सस्ते होंगे।

पीएम ने बताया विश्वास का प्रतीक

प्रधानमंत्री ने इस समझौते को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि में योगदान देने वाला बताया और कहा कि यह समझौता दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए विश्वास का प्रतीक है।÷ उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश 'विजन 2035' के तहत रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे। यह रोडमैप टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, शिक्षा और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देगा।

संसद में विपक्ष की नारेबाजी स्पीकर बोले-

तख्तियां लाने पर सदन नहीं चलेगा लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट चली

राज्यसभा की कार्यवाही 25 जुलाई तक स्थगित

एजेंसी।

सांसद मनोज झा ने 'संविधान की हत्या बंद करो' लिखे पोस्टर लहराए। उनके साथ प्रियंका चतुर्वेदी और जॉन ब्रिटास भी नजर आए। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने बिहार में SIR मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। जिसके बाद सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित - दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फि र हंगामा कर दिया। जिसके बाद सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

रविशंकर प्रसाद बोले- हम चर्चा को तैयार, वे भाग रहे

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्ष और खासकर कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही है। वे बाहर आकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वे सदन में चर्चा में भाग नहीं लेते, इसका क्या मतलब है? हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वे चर्चा से भाग रहे हैं।

रामदास अठावले बोले- बिहार में तेजस्वी ने पहले ही हार मान ली - बिहार SIR के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, अगर वे (तेजस्वी यादव) चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे हार मान रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बुधवार शाम कहा था कि विपक्ष विधानसभा चुनाव का बायकॉट कर सकता है। इसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे।

राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म -

राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। इनमें एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, वाइको, पी विल्सन शामिल हैं। पांचों सांसदों ने सदन में विदाई भाषण दिया।

कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर ईडी ने की छापेमारी, मुंबई में चल रही है कार्रवाई

एजेंसी

मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुंबई में की जा रही है। बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। ये कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी , बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर की गई। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है।

जानकारी के मुताबिक ईडी को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले हैं कि यह सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें कई संस्थानों, बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को ठगा गया। इसमें यस बैंक के प्रमोटर्स भी शक के घेरे में हैं। साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध तरीके से हेराफेरी और दुरुपयोग का शक है।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यमुना उफान पर, पहाड़ों में भूस्खलन से तबाही

देश भर में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली - देश भर में मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से खतरे के निशान तक पहुँच गया है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद

जलस्तर के और ऊपर जाने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह-जगह से भूस्खलन और बादल फटने की दर्दनाक खबरें आ रही हैं। हिमाचल में दो राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) समेत कुल 385 सड़कें मलबे के कारण बंद हो गई हैं। मंडी में एनएच-70 (मंडी-कोटली मार्ग) और सिरमौर में एनएच-707 (हाटकोटी से पांवटा साहिब) कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बाधित है। दोनों राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 12 दोषियों की रिहाई टली

नई दिल्ली ,एजेंसी - 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम रोक लगाई। इस फैसले के बाद अब दोषियों की जेल से रिहाई टल गई है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात सिलसिलेवार बम धमाकों में 187 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 2015 में एक विशेष मकोका अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था।

भारत और यूके आने वाले दशक में वैश्विक विकास की नई कहानी लिखने को तैयार : पीयूष गोयल

एजेंसी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया कि ÷यह समझौता महिलाओं, MSMEs, किसानों और श्रमिकों के लिए समृद्धि का नया द्वार खोलेगा। भारत की सेवा और तकनीकी प्रतिभा को UK जैसे हाई-वैल्यू मार्केट्स में प्रवेश मिलेगा। स्टार्टअप्स को ग्लोबल विस्तार का मौका मिलेगा।÷ India-UK FTA केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह नई वैश्विक साझेदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण की ओर बढ़ता कदम है।

Vision 2035 और इस ऐतिहासिक समझौते के ज़रिए भारत और यूके आने वाले दशक में वैश्विक विकास की नई कहानी लिखने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की साझा क्रिकेट विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि ÷Cricket is not just a game, but a passion. Its a great metaphor for our partnership... हम हमेशा Straight Bat से खेलते हैं।÷ अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री स्टार्मर को भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा कि उन्हें भारत में स्वागत करने का बेसब्री से इंतज़ार है।

विदेश

14 फरवरी 2026 को हिंदी और वियतनामी में होगी रिलीज,

भारत-वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय फिल्म की घोषणा

एजेंसी

नई दिल्ली, भारत और वियतनाम की गहराती सांस्कृतिक साझेदारी को सिनेमा के ज़रिए एक नया आयाम देने जा रही है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) संस्था ने आज वुओन थिन इयु – प्रेम की सुरधारा नामक अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की घोषणा की, जो दुनिया की पहली ऐसी फिल्म होगी जो भारत-वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित होगी।यह ऐतिहासिक घोषणा नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें भारत और वियतनाम के प्रमुख सांस्कृतिक प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कलाकारों ने भाग लिया।इस अवसर पर

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने फिल्म निर्माण की औपचारिक घोषणा की। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे। प्रो. चू बाओ क्वे, अध्यक्ष नीति और विकास परामर्श परिषद, वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशंस (VFUA) त्रुआंग क्वांग हय , निदेशक संस्कृति, खेल व पर्यटन विभाग, बक निन्ह प्रांत, वियतनाम। डॉ. गुयेन होआंग आन्ह (जूलिया गुयेन) , उपाध्यक्ष – वियतनाम रिकॉर्ड्स संगठन, और महासचिव – वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन । भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। इनमें संचिता कुलकर्णी, किशोरी शहाणे, विमल मिश्रा, बिस्वदीप रॉय चौधरी और सितारे ज़मीन पर फेम गोपी कृष्णन वर्मा प्रमुख थे। यह फिल्म द गार्जियन ऑफ हेरिटेज नामक पुस्तक से प्रेरित है, और 7वीं सदी की चाम सभ्यता के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत करेगी। फिल्म में भारत और वियतनाम की समृद्ध कलाओं, संगीत और सांस्कृतिक मूल्यों को खूबसूरती से पिरोया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश : ब्रिटेन खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करें

एजेंसी

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से चरमपंथी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफएक्शन लेने की अपील की।

उन्होंने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात के दौरान कहा कि जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि आजादी के नाम पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। मोदी ने यह बात ऐसे समय में कही जब ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों का असर बढ़ रहा है। मोदी ने आज ब्रिटेन के चेकर्स एस्टेट में ब्रिटिश पीएम के साथ यंग क्रिकेटर्स से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की भूमिका पर चर्चा की।

मोदी ने आज ब्रिटेन के चेकर्स एस्टेट में ब्रिटिश पीएम के साथ यंग क्रिकेटर्स से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की भूमिका पर चर्चा की।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री स्टार्मर और उनकी सरकार के आभारी हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह के दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत से भागे हुए आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए ब्रिटेन को सहयोग करना चाहिए। भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है। समझौते के बाद नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई। उन्होंने भारत- इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का भी जिक्र किया।

मोदी ने कहा कि यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। मोदी ने स्टार्मर को भारत आने का न्योता दिया।

थाईलैंड-कंबोडिया ने एक-दूसरे पर दागे रॉकेट, 9 की मौत

,एजेंसी । बैंकॉक ,24 जुलाई । रूस-यूक्रेन और मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच अब दक्षिण-पूर्व एशिया में भी एक नया युद्ध छिड़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव खतरनाक रूप से बढ़ गया है और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर भीषण गोलाबारी और रॉकेट से हमले शुरू कर दिए हैं। एपी न्यूज के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग घायल हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के एक गैस स्टेशन को BM-21 रॉकेट से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिसके बाद बैंकॉक में हड़कंप मच गया। हमलों के दौरान थाई सैनिकों के जान बचाने के लिए जमीन पर लेटे होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपुष्ट रिपोर्टों में

मरने वालों की संख्या 14 बताई जा रही है, जिसमें कई स्कूली बच्चे और आम नागरिक भी शामिल हैं।

दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने के बाद थाईलैंड में स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक तत्काल सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, थाईलैंड और कंबोडिया में 24 जुलाई को रॉकेट और आर्टिलरी गन से हमले की सूचना मिली है। सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वे तत्काल इलाका खाली कर दें।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जिले के 20357 हितग्राहियों को 10 करोड़ 17 लाख 85 हजार रुपए का हुआ भुगतान

केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संवरता गायत्री का जीवन

महासमुंद, लोकशक्ति।

इमली भाठा, महासमुंद की रहने वाली गायत्री देवांगन एक साधारण लेकिन सजग महिला हैं, उनका जीवन और परिवार केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह न केवल एक कुशल गृहिणी हैं, बल्कि समाज की उन महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने योजनाओं की जानकारी लेकर उनका भरपूर लाभ उठाया और अपने परिवार को सशक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाया।

गायत्री ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त की। इस राशि का उपयोग उन्होंने प्रसव पूर्व पोषण और स्वास्थ्य जांच में किया, जिससे गर्भावस्था के दौरान बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सकी। इस योजना से उन्हें 5 हजार की सहायता दो किस्तों में प्राप्त हुई। इसी तरह राज्य सरकार की कौशल्या मातृत्व सहायता योजना के तहत गायत्री को दूसरी बार गर्भधारण पर अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त हुई। इस योजना से दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है ताकि मातृ के दौरान आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इससे उन्हें 6 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकारी की महती योजना महतारी वंदन के तहत उन्हें हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है। इस राशि से वे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और रसोई खर्च जैसे छोटे-छोटे ज़रूरतें पूरी करती हैं। गायत्री मानती हैं कि यह योजना उनके परिवार की मासिक मदद बन गई है। दो बेटियों की मां गायत्री ने नोनी सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का बड़ा कदम उठाया। बेटियों के जन्म के साथ ही उनके नाम पर नवजात कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 साल तक 5-5 हजार रुपए की राशि जमा की गई, जो उन्हें भविष्य में शिक्षा और

आत्मनिर्भरता की दिशा में सहारा देगी। 18 वर्ष के पश्चात एक लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। गायत्री के पति एक वेल्डर हैं। आय सीमित होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गायत्री ने आंगनबाड़ी से जुड़कर न केवल पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की, बल्कि अन्य महिलाओं को भी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। आज गायत्री का परिवार संतुलित पोषण, सुरक्षित मातृत्व और बालिका शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वे कहती हैं अगर हम योजनाओं की जानकारी लें और उनका सही उपयोग करें, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले में विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है जिसके अंतर्गत पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में 3 हजार रूपये एवं दूसरी किस्त 2 हजार रूपये प्रसव के बाद व शिशु का टीकाकरण होने पर मिलता है। महिलाए एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकवेन्द्र जटवार ने बताया कि जिले में सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजनांतर्गत कुल 17075 हितग्राहियों के आवेदन के विरूद्ध 3282 बैकलाग हितग्राही सहित 20357 हितग्राहियों को 10 करोड़ 17 लाख 85 हजार रूपये भुगतान किया गया है।

उन्होंने सत्रवार जानकारी देते हुए बताया कि जिले में योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज 7330 हितग्राहियों के विरूद्ध 3627 हितग्राहियों को राशि भुगतान, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज 8227 हितग्राहियों के विरूद्ध 14722 हितग्राहियों को राशि भुगतान एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज 1518 हितग्राहियों के विरूद्ध 2008 हितग्राहियों को राशि भुगतान पी.एफएम.एस. से डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया गया है। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से अथवा स्वयं अपना ऑनलाईन पंजीयन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

जनपद पंचायत सदस्यों का तीन दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न

कांकेर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मण्डावी के मार्गदर्शन में विकासखंड कांकेर, भानुप्रतापपुर, चारामा एवं नरहरपुर के जनपद पंचायत सदस्यों की 03 दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पंकज कुमार सिन्हा, संकाय सदस्य कमलेश कुमार साहू एवं वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी राजेन्द्र राठौर के द्वारा 73वां संविधान संशोधन, जनपद पंचायत सदस्यों के कर्तव्य एवं अधिकार तथा कामकाज संचालन प्रक्रिया, पेसा कानून एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज सहित सभी विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के प्राचार्य ने कहा कि पंचायती राज संरचना के महत्वपूर्ण एवं आधारभूत जानकारी के साथ ही सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा में सार्थक होगा। पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के सशक्तिकरण में जनपद पंचायत सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

0 जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में निःशुल्क डायलिसिस सेवा

0 डायलिसिस के लिए संपर्क नंबर 6267317316, 9329205242

सारंगढ़ बिलाईगढ़, कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत् जीवनधारा निःशुल्क डायलिसिस सेवा का सफल संचालन किया जा रहा है। क्रोनिक किडनी के मरीजों में खून की कमी, मूत्र में रक्त आना।

कुरुद में 1 अगस्त को आयोजित होगा उद्यम से विकास तक युवा उद्यमी एवं स्टार्टअप सम्मेलन

0 ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ, इच्छुक विद्यार्थी, युवा, उद्यमी और नागरिक कर सकते हैं भागीदारी

0 विकास की दिशा, नवाचार की प्रेरणा धमतरी से उद्यम की शुरुआत!

धमतरी, आरएनएस)। धमतरी जिले में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा उद्यम से विकास तक कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत अगला सत्र 01 अगस्त 2025 को कुरुद में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और नवाचार में रुचि रखने वालों को स्टार्टअप्स और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ना है। जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के विद्यार्थियों, युवाओं, महिला उद्यमियों एवं इच्छुक नागरिकों से सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने सभी से अग्रिम ऑनलाइन पंजीयन हेतु गूगल फॉर्म लिंक पर जाकर पंजीकरण करने का आग्रह किया है।

सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यः

युवाओं और नवाचारकर्ताओं को उद्यमिता के प्रति प्रेरित करना, स्टार्टअप व व्यवसायिक कौशल का विकास विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता की जानकारी प्रदान करना। प्रतिभागियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।

आयोजन सहयोगी संस्थानः

कार्यक्रम का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नेतृत्व में, सीजीएस नेटवर्क रायपुर, सफल उद्यमियों, स्टार्टअप विशेषज्ञों सीजीएस और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है।

प्रमुख संभावित प्रतिभागीः

वर्तमान उद्यमी एवं स्टार्टअप संस्थापक, बिहान, डीटीआईसी, पीएमईजीपी, स्टार्टअप योजना के लाभार्थी, बैंक ऋण / योजना में आवेदनकर्ता, नवाचार में रुचि रखने वाले छात्र, युवा, महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के इच्छुक उद्यमी, वे आम नागरिक जो स्टार्टअप या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं।

विचार, योजनाएं एवं प्रोजेक्ट आमंत्रितः कार्यक्रम के अंतर्गत युवा नवप्रवर्तकों से आइडियाज, योजनाएं एवं परियोजनाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक प्रतिभागी मार्गदर्शन हेतु निम्न विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैंः

विशेषज्ञ संपर्क विवरणः

जिला उद्योग केंद्र, धमतरी

प्रशांत चंद्राकर 81037 18222

कृषि / फूड प्रोसेसिंग / जनजातीय आधारित स्टार्टअप्स

दुर्गेश गंजीर 96852 84545

आशीष पुरैना 98263 00736

आईटी / फिनटेक / मीडिया / सेवा / पेट्रोलियम / शिक्षा

संजय पटेल 88893 45113

नरेश बंजारे 78287 11116

उमेश महिलानी 93017 27212

देवानंद गेंदले 88894 49490।

कुम्हारराास नर्सिंग कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

दंतेवाड़ा, कुम्हारराास नर्सिंग कॉलेज में आज मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य छात्रों और स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और आत्म-सहायता के व्यावहारिक उपायों के प्रति जागरूक करना था। इस जागरूकता शिविर का संचालन जिला अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. देश दीपक एवं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य लेकिन गंभीर समस्याओं जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, व्यवहार संबंधी चुनौतियां एवं उनसे निपटने के परामर्श तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, डॉ. देश दीपक ने न्यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसे मिर्गी, स्ट्रोक, माइग्रेन, सिरदर्द, पार्किंसन रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों पर भी व्याख्यान दिया, जिससे विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक पहचान और उपचार की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने आत्म-सहायता की तकनीकों, नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और संवाद की भूमिका पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर पोस्टर प्रदर्शनी, समूह चर्चा और ध्यान अभ्यास जैसी विविध गतिविधियां भी आयोजित की गयी, जिनके माध्यम से प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिला।

एसपी के निर्देश पर जिलेभर में लॉज, होटल, बार एवं ढाबों की आकस्मिक चेकिंग

0 संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम हेतु थाना प्रभारियों ने दिए आवश्यक निर्देश

0 आस-पास कोई संदिग्ध बंग्लादेशी या रोहिंग्या निवासरत है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-233- 1905पर करें साझा

धमतरी, पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गुरुवार को देर रात लॉज, होटल, ढाबा एवं विश्रामगृहों की आकस्मिक चेकिंग की गई। यह अभियान सार्वजनिक सुरक्षा,असामाजिक तत्वों की निगरानी एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूर्व में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित सभी लॉज,होटल,ढाबों में समय-समय पर सतत निगरानी रखते हुए चेकिंग करें तथा वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, पहचान पत्र, आगंतुक रजिस्टर आदि का सूक्ष्म निरीक्षण करें।

जांच के दौरान मुख्य रूप से देखे गए बिंदुः लॉज/होटल में रुकने वाले व्यक्तियों का वैध पहचान पत्र व रजिस्टर में नाम दर्ज है या नहीं। सीसीटीवी कैमरों की स्थिति-कार्यशील हैं या नहीं। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कोई व्यक्ति तो नहीं। ढाबों में रात्रि विश्राम करने वाले वाहन चालकों व अन्य व्यक्तियों की जानकारी। होटल/ढाबा संचालकों को असामाजिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया।

सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर यह अभियान चलाया गया, जिसमें थाने की टीमों ने संवेदनशील स्थानों को प्राथमिकता देते हुए गहन चेकिंग की।

महत्वपूर्ण निर्देशः

सभी होटल, लॉज एवं ढाबा संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि

बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को रुकने की अनुमति न दें। सीसीटीवी कैमरे हर हाल में चालू हालत में रहें। आगंतुक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जाए। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न

0 जिले में गरिमामय पूर्ण रूप से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस

0 स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु विभागों को सौंपे गए दायित्व

0 जिला पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों की संख्या बढ़ाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पंजीयन में प्रगति लाने के लिए कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश

दंतेवाड़ा, कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम आगामी स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक तैयारियां के रूप रेखा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इसके अनुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का दंतेवाड़ा में गरिमामय पूर्ण रूप से आयोजित किया जायेगा। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा पुलिस एवं नगर सैनिकों की टुकड़ियों द्वारा सलामी ली जाएगी।

मुख्य अतिथि द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन हेतु पूर्व की भांति अन्य विभागों को दायित्व सौंपे गये। इस संबंध मे आगे कहा गया कि जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष और नगरी निकायों में नगरीय निकायों के अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। तथा स्कूली बच्चो के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे साथ ही सभी शासकीय भवनों, स्मारकों में रोशनी की जाएगी। अन्य वर्ष की तरह शासकीय भवनों, ऐतिहासिक स्थानों के साथ-साथ निजी संस्थानों में भी राष्ट्रीय झंडा वंदन होगें।

बैठक में इसके अलावा आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन की आवश्यक रूपरेखा तैयार कर विभागवार दायित्व सौंपा गया। इसके अन्तर्गत मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन, उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने, कार्यक्रम में पेयजल, चिकित्सा, स्वल्पाहार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों,, मंच स्थल की साज-सज्जा, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, वन विभाग, आदिम जाति विभाग, जिला पंचायत, खाद्य विभाग को दायित्व सौंपे गए। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि उत्कृष्टता पूर्वक शासकीय कार्य संपादित किया जाना इसका मापदंड निर्धारित किया जाए। साथ ही आमंत्रण कार्ड में प्रिंटिंग एवं वितरण में सभी नगरीय एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों का नाम उल्लेख प्रोटोकॉल अनुसार निश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही 13 अगस्त को 15 अगस्त समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल में भी सभी अधिकारी उपस्थित रहेगें।

पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी, भावनात्मक लगाव के साथ पौधे अवश्य लगाएं : विधायक नेताम

0 जिला स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम कोदागांव से

0 विधायक एवं कलेक्टर ने शाला परिसर में लगाए नारियल व कटहल के पौधे

कांकेर,। 'एक पेड़ मां के नाम-2.0' के तहत आज कांकेर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोदागांव में जिला स्तरीय पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नेताम ने कहा कि मानव जीवन में पेड़ का बड़ा महत्व है। आज के दौर में पौधे लगाना बहुत जरूरी है, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेड़ों से भावनात्मक लगाव होना भी आवश्यक है। ग्राम कोदागांव के विशाल शाला परिसर में आयोजित जिला स्तरीय सामूहिक पौधरोपण कार्यक्रम में विधायक ने आगे कहा कि लोगों को अपने या अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ जैसे अवसरों को यादगार बनाने पौधे जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करने के संकल्प को आगे बढ़ाने का अनुरोध ग्रामीणों से किया। इस अवसर पर मौजूद कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान) में लगातार वृद्धि हो रही है जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वर्षा की अनियमितता, पर्यावरण असंतुलन, तापमान में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए पौधे लगाना आज के समय की मांग है। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम-2.0' के तहत अच्छी नस्ल के पौधे लगाकर पर्यावरण और प्रकृति को सुरक्षित व संरक्षित करने की अपील की। इस अवसर पर विधायक ने विद्यालय परिसर में नारियल, कलेक्टर ने कटहल का पौधा लगाकर उन्हें पानी से सींचा। तत्पश्चात सभी अतिथियों और ग्रामीणों ने 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' के अंतर्गत एक-एक पौधे लगाकर प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड एवं हस्त शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी, उपाध्यक्ष श्रीमती ताराबती ठाकुर, जनपद पंचायत कांकेर की अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा कावड़े, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, पंचूराम नायक सहित स्थानीय सरपंच के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध

0 परीक्षा में आधी बांह के कपड़े पहनने की अनुमति

0 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कान में गहने प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में 27 जुलाई रविवार को आयोजित होने वाले आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र अपलोड किया जा चुका है। व्यापम की यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक निर्धारित है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 4361अभ्यर्थी शामिल होंगे। वेबसाइट व्यापमसीजी डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन है।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूर्व परीक्षार्थी की होगी जांच :

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा हाथों से तलाशी, फ्रिस्किंग किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में आबंटित एक पुरुष एवं एक महिला पुलिस कर्मी से यह फ्रिस्किंग कार्य किया जाना है। ये पुलिस कर्मी परीक्षा प्रारंभ होने से 2.30 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देंगे। महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मी से ही कराया जाना है। व्यापम के निर्देशों का पालन ना करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूर्व सावधानियां

परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। पैर में चप्पल पहन कर जाएं। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सुबह 10.45 बजे परीक्षा केंद्र का गेट हो जाएगा बंद

परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। यह परीक्षा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो मुख्य द्वार प्रातः 10.45 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित है।

ओरिजनल पहचान पत्र से मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश

प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट ले और पेज के केवल एक तरफप्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी।

27 को होगी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा

आबकारी आरक्षक परीक्षा प्रवेश पत्र के संबंध में जारी हुए विशेष दिशा निर्देश

दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा (एबीए 25) का आयोजन 27 जुलाई 2025 दिन रविवार समय 11 से 1:15 बजे को किया जावेगा। इस संबंध में अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र दिनांक 21 जुलाई 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस के यू.आर.एल. को क्लिक करके भी सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग दो घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं फ्रिस्किंग के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हो जावें। प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। किसी

भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचेगें ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात् प्रातः 10: 30 बजे परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा।

समन्वित प्रयासों से निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने कहा–सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करें

रायपुर, लोकशक्ति।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काउ-कैचर जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों की वर्तमान उपयोगिता, क्षमता और सुधार की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा की और सुझाव माँगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित गांवों में पशुओं के प्रबंधन हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनती है, अतः इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई आवश्यक है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों और उनमें निराश्रित पशुओं की भूमिका की समीक्षा की गई। साथ ही, गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निराश्रित एवं लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने की बात कही।

नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम के लिए काउ-कैचर की कार्यप्रणाली और उसके विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेशभर की गौठानों, गौशालाओं एवं पशुधन विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद एवं श्री राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजधानी में हुई भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त

पौन घंटे में 31 एमएम वर्षा होने से कई मोहल्ले एवं बस्तियां जलमग्न

रायपुर, राजधानी में आज सुबह एक इंच के आसपास वर्षा होने के कारण पूरा शहर तरबतर हो गया। नालियों की साफ सफाई की पोल खुल गई। वहीं सड़कों में पानी भर गया। जिसके कारण सुबह काम में जाने वाले लोग काफी परेशान हो गये। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिण बस्तर में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. चंद्रा से मिली जानकारी के अनुसार ऊपर हवा में चक्रवात एवं मानसून द्रोणिका तथा बस्तर के ऊपर एक चक्रवात बनने के कारण आज राजधानी में दस बजे से लेकर 11 बजे के बीच काफी वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यहां पर आधे घंटे में एक इंच के आसपास वर्षा हुई है। मौसम विभाग के रिकार्ड के अनुसार 31.5 एमएम वर्षा होने के कारण राजधानी के कई पाश इलाके में पानी भर गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार चौबे कालोनी, समता, प्रोफेसर कालोनी तथा जोन क्रमांक एक के अंतर्गत आने वाले देवेंद्र नगर तथा अन्य निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार एक वर्षा सिर्फ राजधानी के सीमित क्षेत्र में हुई है जबकि माना के आसपास कोई वर्षा नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून द्रोणिका एवं ऊपरी हवा में चक्रवात होने के कारण दक्षिण बस्तर में अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। आज वर्षा होने के पश्चात राजधानी के पार्षद तथा जोन कमिश्नर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने पहुंचे। जयस्तंभ चौक काफी हाउस के सामने भावना नगर काली नगर, गीता नगर सहित अन्य निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। वहीं खारून नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही वर्षा होने के कारण राजधानीवासी काफी परेशान रहे। कामकाजी लोगों को काफी परेशानी हुई।

मुख्यमंत्री साय ने लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर किया नमन

लोकशक्ति रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती (23 जुलाई) के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए इन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा जैसे क्रांतिकारी उद्घोष के माध्यम से जनमानस में आज़ादी के लिए चेतना की ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने सामाजिक समरसता के उद्देश्य से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की सार्वजनिक परंपरा की शुरुआत कर राष्ट्रीय एकता को एक नया सांस्कृतिक आधार प्रदान किया।

साय ने चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता संग्राम की ज्वलंत प्रेरणा हैं। आजाद ने अपना जीवन देश को समर्पित कर युवाओं में आत्मबल, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को जाग्रत किया। उनका नाम ही देशभक्ति, अदम्य साहस और संकल्प का प्रतीक बन गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलक जी और आजाद जी का संघर्ष और बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्तंभ हैं। उनके विचार, आदर्श और राष्ट्रप्रेम आज भी हम सभी को देश की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

उच्च शिक्षा विभाग में संलग्रीकरण के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा

कालेज में पढ़ाना छोड़कर प्राध्यापक प्रशासनिक पदों पर हो रहे काबिज

रायपुर, । संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग में कई प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक जुगाड़ में अधिक भरोसा रखते है और इसी तर्ज पर अनेक प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक पदों पर लंबे समय से पदस्थ है। एक ओर जहां प्रदेश में महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए प्राध्यापकों की कमी रेखांकित की जाती रही है वहीं रिसर्च और पढ़ाई कराने में प्राध्यापक रूचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकांश प्राध्यापक अध्यापन कार्य को छोड़कर प्रशासनिक पदों पर काबिज होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन के दिशा निर्देशों की अव्हेलना करते हुए कुछ सचिव स्तर के अधिकारी अपने लोगों को प्रशासनिक पदों पर पदस्थ कर उत्कृष्ट किये है। अटेचमेंट और डेपूटेशन का खेल लंबे समय से जारी है। नई शिक्षा नीति महाविद्यालयों के लिए निर्धारित की गई है। उसके तहत समस्त संलग्रीकरण समाप्त कर महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु प्राध्यापकों को मूल विभाग को भेजने के निर्देश दिये गये है इसके बाद भी कई प्राध्यापक अभी भी प्रशासनिक पदों पर जमे हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरह अपने लोगों को उपकृत कर रहे हैं इसका उदाहरण देखने में आया है जब उच्च शिक्षा विभाग ने पांच दिसंबर 2012 को एक आदेश जारी किया था जिसमें 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक एवं प्राचार्यों को प्रशासनिक पदों पर पदस्थ नहीं किया जा सकता। उक्त नियम का भी लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।

इसी तरह राजलक्ष्मी सेलट को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय अटारी जिला रायपुर के लिए पदस्थापना आदेश जारी किया गया था। आदेश जारी होने के ठीक एक हफ्ते बाद उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उक्त आदेश के मद्देनजर भी उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक के पद पर पदस्थ है। डॉ. एचपी खैरवार को जो पीजी प्रिंसिपल है को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर शासकीय एमएमआर पीजी महाविद्यालय जांजगीर चांपा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया। विभागीय आदेश के बिना उन्हें एकतरफा रिलीव किया गया। अब वे अपर संचालक के पद पर नहीं है। उक्त शिक्षा विभाग के ये दो स्थानांतरण शासन की दोहरी स्थानांतरण नीति को प्रकट करते हैं।

अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार

रायपुर, (आरएनएस)। पुरानी बस्ती और खरोरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 56 पाव देशी शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दर्री तालाब के पास भाठागांव में दबिश देकर आरोपी ललीत गोडाने 20 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 39 पाव देशी शराब जब्त किया है।

मंदिर के दानपेटी से नकदी रकम पार

रायपुर, सुंदरेश्वर महादेव मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने दानपेटी से 8 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसा प्रार्थी हेमंत राव कामडे 41 वर्ष सुंदर विहार कालोनी रायपुरा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि उसके घर के पास स्थित सुंदरेश्वर महादेव मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने दानपेटी से 8 हजार रुपए पार कर दिया।

एबीवीपी रायपुर महानगर ने किया नवदीप सम्मान समारोह का आयोजन

रायपुर, । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रायपुर महानगर द्वारा मंगलवार को शहीद स्मारक भवन में नवदीप छात्र सम्मान समारोह एवं विशेष करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर जिले के 60 से अधिक विद्यालयों से लगभग 650 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। साथ ही एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवकों की भी सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी भिलाई के निदेशक डॉ. राजीव प्रकाश उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को करियर मार्गदर्शन देते हुए कहा कि आईआईटी जैसे संस्थान सभी स्कूली विद्यार्थियों के लिए खुले हैं। अगर संकल्प और परिश्रम हो, तो कोई भी मंज़िल दूर नहीं।

विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक टोपलाल वर्मा ने छात्रों को जीवन के 'पंच परिवर्तन' (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक) पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशुतोष मंडावी ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एनईपी विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक, बल्कि नैतिक, कौशल आधारित और व्यावसायिक दृष्टि से भी संपूर्ण विकास का अवसर देती है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा सोना जितना तपता है, उतना ही अधिक निखरता है। विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयों का सामना ही चरित्र निर्माण की नींव है।

रायपुर महानगर मंत्री श्री प्रथम राव फुटाने ने एबीवीपी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि अभावों से समाधान तक की यात्रा में एबीवीपी हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी।

कार्यक्रम के दौरान रायपुर जिले के तीन टॉप छात्र-छात्राएं पल्लवी वर्मा, कृष्ण पंजवानी और कृति यादव का सम्मान किया गया। साथ ही प्रदेश स्तर के बोर्ड टॉपर्स, खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र, तथा एनसीसी/एनएसएस में विशेष योगदान देने वाले प्रतिभागियों को भी मंच पर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का समापन रायपुर महानगर अध्यक्ष डॉ. अनुज शुक्ला के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने एबीवीपी की छात्रोन्मुख कार्यशैली और समाज निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

अंत में वंदे मातरम् गीत के साथ राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत वातावरण में समारोह का समापन हुआ।

स्टेट कैपिटल रीजन : छत्तीसगढ़ का बनेगा नया ग्रोथ इंजन

जी.एस. केशरवानी, उप संचालक

सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

रायपुर, 2 राजधानी रायपुर और उसके आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ ईंजन बनेगा। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन' ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित होगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के केन्द्र में स्थित होने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल पर स्टेट कैपिटल रीजन में योजनाबद्ध और शहरी विकास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे राजधानी और आसपास के शहरों का प्लान्ड डेव्हलपमेंट होगा। साथ ही शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी।

स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहरों में वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की आबादी रहने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के अनुरूप होगा।

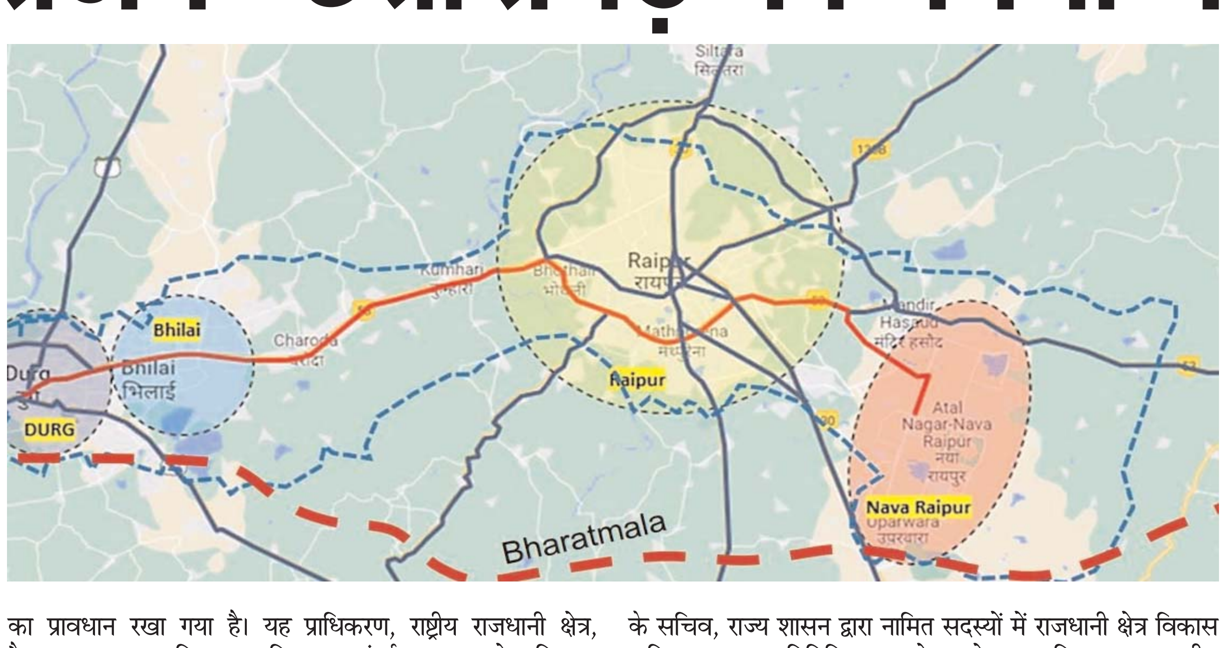

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य शासन द्वारा नामित सदस्यों में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विधायक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निर्वाचित सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके सदस्य संयोजक होंगे।

यह प्राधिकरण भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना के लिए सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य राजधानी और आसपास के शहरों के व्यापक विकास के लिए योजना बनाने के साथ नियामक और समन्वय सस्थान के रूप में कार्य करना है। इसके प्रमुख कार्यों में स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाना, निवेश, आर्थिक योजनाओं और इनका कार्यान्वयन, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना भी है।

प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग के विकास संचालक, शहरी योजनाकार, अभियंता, वित्त, संपदा, पर्यावरण नामांकित सदस्य होंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के कलेक्टर इसके सदस्य होंगे। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक पुनरावृत्ति निधि भी होगी। इसे राजधानी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने की शक्ति भी होगी। यह वार्षिक बजट भी तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

संपादकीय

आतंकी संगठनों से बड़ा खतरा

वैश्विक स्तर पर किए गए अध्ययन मानते हैं कि बीते छह सालों में आतंकवादी घटनाओं में 32 प्रतिशत इजाफा हुआ है। अकेले 2021 के दौरान दुनिया भर में पांच हजार से ज्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई जिनमें हजारों मासूम जानें तो जाती ही हैं, दहशत की माहौल भी बढ़ता है। ढेरों परिवार उजड़ जाते हैं। 2018-21 के दरम्यान अकेले भारत में आठ हजार के करीब जान गई। दक्षिण एशियाई देश यूं भी आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं हैं।

यहां सीमापार उग्रवाद को रोकना बड़ी चुनौती है। खासकर भारत के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल रहे आतंकी संगठनों से बड़ा खतरा है, जो बड़ी संख्या में आतंकियों को घुसपैठ कराने का जाल मजबूत करता रहता है। भूलना नहीं चाहिए कि आतंकियों को कानूनी भय नहीं दिखाया जा सकता। उसके लिए बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सेना व स्थानीय पुलिस को काम करने की आजादी दी जानी जरूरी है। धनशोधन को लेकर भी पर्याप्त सतर्कता जरूरी है।

संभावनाओं से परिपूर्ण गिग-अर्थव्यवस्था

लेखक: डा मनमोहन प्रकाश , स्वतंत्र पत्रकार

गिग-अर्थव्यवस्था भारत में एक उभरती हुई लचीली आर्थिक प्रणाली के रूप में तेजी से विकसित हो रही है, जिसमें कार्य आधारित, अल्पकालिक और स्वतंत्र रोजगार अवसर डिजिटल प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। गिग-वर्कर - जिन्हें फ्रीलांसर, स्वतंत्र पेशेवर या कॉन्ट्रैक्ट-आधारित कर्मचारी भी कहा जाता है,पारंपरकि नौकरियों के स्थान पर किसी विशेष कार्य या सेवा के लिए अनुबंधित किए जाते हैं और उन्हें उस कार्य के अनुसार भुगतान प्राप्त होता है।

नीति आयोग की एक रपट के अनुसार, भारत की गिग-अर्थव्यवस्था 2030 तक लगभग 9 करोड़ (90 मिलियन) नौकरियों का सृजन कर सकती है और यह देश की जीडीपी में 1.25% तक का योगदान दे सकती है। यह अनुमान दर्शाता है कि यदि उचित नीति समर्थन मिले, तो गिग-अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण इंजन बन सकती है।

भारतीय युवा और गिग-अर्थव्यवस्था: निम्न कारणों की वजह से यह अर्थव्यवस्था आज के समय में कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई है -

(1) रोजगार के अवसरों में विस्तार: गिग-अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। कम कौशल या अर्ध-कुशल युवाओं को अब पारंपरकि नौकरियों के अभाव में भी सम्मानजनक कार्य और आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। फूड डिलीवरी, राइड-शेयरिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक कई क्षेत्रों में गिग-वर्कर्स की मांग तेजी से बढ़ी है।

(2)उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता: गिग-वर्क केवल आय अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमशीलता का मंच भी बन गया है। अनेक युवा आज फ्रीलांसिंग को मुख्य पेशा बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यह स्वतंत्रता उन्हें अपने कार्यक्षेत्र और क्लाइंट्स का चुनाव करने की शक्ति देती है एक ऐसा लचीलापन जो पारंपरकि नौकरियों में संभव नहीं।

(3)लचीलापन और जीवन संतुलन: गिग-कार्य युवाओं को समय और स्थान की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह लचीलापन उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ बेहतर तालमेल बैठाने में मदद करता है। विशेष रूप से महिलाएं, दिव्यांगजन और सीमांत समुदायों के लोग इस मॉडल से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

(4) डिजिटल दक्षता और तकनीकी सशक्तिकरण:भारत के युवाओं की डिजिटल समझ और तकनीकी रुचि ने उन्हें गिग-कार्यों के लिए उपयुक्त बना दिया है। डिजिटलीकरण और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच ने गिग-प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, अर्बन क्लेप, स्विगी,जूमेटो आदि को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है, जिससे यह अवसर अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहे। गिग-अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ:हालांकि यह व्यवस्था संभावनाओं से भरपूर है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी सामने हैं:

(i) सामाजिक सुरक्षा का अभाव: गिग-वर्कर्स को बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ या चिकित्सा सहायता जैसे सुविधाएं प्रायः प्राप्त नहीं होती है।

(ii)आय की अनिश्चितता: गिग-कार्यों में आय नियमित नहीं होती, जिससे दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाना कठिन होता है।

(iii) कार्य-शोषण की आशंका: अनुबंध आधारित कार्यों में कंपनियां श्रमिक अधिकारों को अक्सर नज़र-अंदाज़ करती हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता और कार्यकर्ता की संतुष्टि दोनों प्रभावित होती हैं।

निष्कर्ष: गिग-अर्थव्यवस्था भारत के युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग लेकर आई है। यह डिजिटल युग में युवाओं को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप अवसर खोजने और उन्हें साकार करने का मंच प्रदान करती है। हालांकि, इसके स्थायी और सुरक्षित विकास हेतु आवश्यक है कि सरकार श्रम कानूनों में संशोधन कर गिग-वर्कर्स को भी न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करे। यदि ऐसा होता है, तो यह व्यवस्था भारत को युवा शक्ति के बल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकती है।

भूखमरी है विकास के विरोधाभासी स्वरूप की भयावह तस्वीर

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की हालिया रिपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक समुदाय को चेताया है कि धरती पर करोड़ों लोग आज भी भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक वैश्विक त्रासदी की दास्तान है, जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि इक्कीसवीं सदी के इस तथाकथित 'विकसित' दौर में भी हम उस प्राथमिक आवश्यकता-भोजन को सुनिश्चित नहीं कर सके हैं, जो किसी भी आदर्श शासन-व्यवस्था एवं सभ्यता की बुनियादी कसौटी है। एफएओ के अनुसार, दुनिया भर में 70 करोड़ से अधिक लोग गंभीर भूख का शिकार हैं, जबकि करीब 2 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हालात और भी बदतर हैं। बच्चों में कुपोषण और स्टंटिंग (विकास अवरोध) की दरें चिंताजनक हैं।

समूची दुनिया में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जैसी तकनीक की नई-नई मिसाल कायम की जा रही हैं। किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर, क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? विकास की इस धारा में इंसान एवं इंसान की मूलभूत जरूरतें कहां है? यह कैसा विकास है कि जिसमें विसंगतियां एवं विरोधाभास ही अधिक है। एक तरफविभिन्न देश तकनीक के सहारे खुद के ताकतवर एवं साधन संपन्न होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बढ़ती भूखमरी एवं कुपोषण आधुनिक विकास पर एक बदनुमा दाग है। इस वैश्विक संकट की जड़ में केवल खाद्यान्न की कमी नहीं, बल्कि युद्ध, आंतरिक संघर्ष, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थितियां गहराई से जिम्मेदार हैं।

यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते गेहूं, तेल, उर्वरक और अन्य खाद्य सामग्री की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान, यमन और सोमालिया जैसे देशों में वर्षों से चल रहे युद्धों ने लाखों लोगों को बेघर, बेरोजगार और भूखा बना दिया है। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष और जलवायु आपदाएं खाद्य संकट को और विकराल बना रही हैं। भुखमरी के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो देशों के बीच युद्ध और आंतरिक संघर्ष प्रमुख है। इन दो कारणों से ही बीस देशों में करीब 14 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। जाहिर है, लगातार जारी युद्धों, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों एवं आतंकवाद की वजह से हालात और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने में भी तरह-तरह की अड़चनों की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने द्योतक हैं।

जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, चक्रवात और असामयिक वर्षा जैसे कारक कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, जैसे देशों के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मानसून के दौरान होने वाली आपदाएं किसानों की मेहनत को तबाह कर देती हैं। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटता है, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की थाली सूखने लगती है। संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर जटिल से जटिलतर हो गई है। रपट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देशों या क्षेत्रों के 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे। यह आंकड़ा वर्ष 2023 के मुकाबले 1.37 करोड़ अधिक है। यानी सुधार के बजाय स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है।

आधुनिक विकास के प्रारूप पर चिन्तन करना होगा। यह विचारणीय प्रश्न है कि विकास के इस प्रारूप में बड़े-बड़े मॉल बन रहे हैं, शहरों में चमचमाती इमारतें खड़ी हो रही हैं, तकनीक और एआई की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। भुखमरी बढ़ रही है, कुपोषण आम होता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने गरीब की थाली से दाल-सब्जी गायब कर दी है। विकास का यह विरोधाभासी चेहरा दिखाता है कि संसाधनों का वितरण असमान है और नीतियां गरीबों की भूख मिटाने की बजाय अमीरों की संपत्ति बढ़ाने में लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) में 2030 तक 'भूखमुक्त विश्व' का सपना देखा गया था, लेकिन वर्तमान हालात यह संकेत दे रहे हैं कि हम इस लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। गरीब देशों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है, लेकिन विकसित राष्ट्र अपने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों में उलझे हुए हैं। कृषि को प्राथमिकता देने के बजाय, हम स्मार्ट सिटी, हाईवे और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में संसाधन झोंक रहे हैं।

महंगाई और बेरोजगारी से उपजी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं। रपट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से पंद्रह देशों में 5.94 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। इसके अलावा, सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.6 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। अधिक चिन्ताजनक यह है कि इन लोगों को खाद्य एवं पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद में भी भारी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि वैश्विक मदद और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सांसें धीरे-धीरे उखड़ रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। इस जटिल से जटिलतर होती समस्या के समाधान के लिये व्यापक प्रयत्नों की अपेक्षा है। इन प्रयत्नों में सबसे जरूरी है कि स्थायी कृषि नीति बनानी होगी जिसमें जल संरक्षण, जैविक खेती और छोटे किसानों की सुरक्षा पर बल दिया जाए। युद्ध और संघर्षों का समाधान कूटनीति और संवाद से निकाला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी कीमत आम जनता चुकाती है। भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार की तरह लागू किया जाए, और सभी देश एक वैश्विक खाद्य भंडारण व वितरण प्रणाली विकसित करें। गरीबी उन्मूलन पर ठोस योजनाएं बने, ताकि लोग आत्मनिर्भर बनें और भीख या राहत पर निर्भर न रहें। महंगाई पर नियंत्रण, और गरीबों को सब्सिडी आधारित खाद्यान्न व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।

एफएओ की रिपोर्ट में एक और भयावह तस्वीर सामने आती है कि दुनिया भर में उनतीस करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल है। साफ है कि समाज का सबसे कमजोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, प्राकृतिक आपदा और जबरन विस्थापन जैसी समस्याओं के चक्रव्यूह में कैद है। यदि हमने समय रहते भूख, गरीबी और खाद्य असुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, तो हम विकास के उस नक्शे पर एक गहरा धब्बा छोड़ेंगे, जिसमें ऊंची इमारतें तो होंगी लेकिन उनके नीचे भूख से दम तोड़ते इंसान भी होंगे। 'एक रोटी की कीमत तब समझ आती है, जब भूख कई रातों से जाग रही हो'-इसलिये अब समय है कि हम विकास के मायने बदलें ताकि हर थाली में भोजन हो, हर बच्चा कुपोषण से मुक्त हो, और भूख इतिहास की बात बन जाए, वर्तमान की नहीं। विकास की इक्कीसवीं सदी में भी अगर भुखमरी, कुपोषण एवं खाद्य संकट की समस्या विकराल होती जा रही है, तो यह व्यवस्था के साथ-साथ मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है। इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि संकटग्रस्त इलाकों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण सेवाओं में निवेश पर जोर दिया जाए। समय आ गया है कि विभिन्न देशों की सरकारें जनकल्याण की योजनाओं की व्यापक समीक्षा करें और भुखमरी को दूर करने के लिए उचित एवं प्रभावी उपाय किए जाएं।

यह निजी विचार है।

अनपेक्षित कतई नहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण

अवधेश कुमार

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण या इंटेंसिव रिवीजन का इलेक्टरल रोल जिस तरह विरोध और हंगामा का विषय बना है वह अनपेक्षित कतई नहीं है।

कांग्रेस पार्टी और अनेक भाजपा विरोधी दल, एक्टिविस्ट, पत्रकार, एनजीओ आदि काफी समय से चुनाव आयोग विरोधी तीखा अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी तो पुनरीक्षण आरंभ होने के पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि हेर-फेर कर भाजपा को जिताने का काम चुनाव आयोग करेगा। विरोधी बार-बार आयोग के विरु द्ध उच्चतम न्यायालय जाते और निराश वापस आते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने इस बार भी पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने की उनकी अपील खारिज कर दिया। हालांकि आगे वह सुनवाई के लिए सहमत हुआ है। सुनवाई के एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया गया। चुनाव आयोग का विज्ञापन कहता है कि गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई है और मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त , 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितम्बर, 2025 को किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि किसी का नाम छूट गया तो दावा करने के लिए एक महीने का समय है।

तो बिना देखे कि किसका नाम जुड़ा, नहीं जुड़ा इस तरह के विरोध का औचित्य क्या है? आयोग पर पहला आरोप है कि वह इतनी जल्दी बड़े प्रदेश के मतदाताओं की सूची कैसे बना लेगा? जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में पुनरीक्षण हुआ था तब 15 जुलाई से 14 अगस्त यानी वर्तमान के अनुसार ही 31 दिन का समय था। क्या 22- 23 वर्ष के बाद मतदाता सूची की गहनता से जांच-परख नहीं होनी चाहिए? अगर चुनाव आयोग ने इसके लिए आवश्यक जनसंपर्क और आधार कार्य नहीं किया तो आलोचना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि पिछले 4 महीने में प्रत्येक विधानसभा, जिला में सर्वदलीय बैठक की गई और लगभग 5 हजार ऐसी बैठकों में 28 हजार लोगों ने भाग लिया।

आयोग ने लगभग 80 हजार बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए हैं जो मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी 1.54 लाख बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। भारी संख्या में स्वयंसेवक भी सक्रिय हैं। कुल 16 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म प्रकाशित किए गए। एक फॉर्म रिसिप्ट के रूप में मतदाता के पास रहेगा और दूसरा बीएलओ रखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर भी फॉर्म जमा करने की व्यवस्था है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि ड्राइव बिल्कुल अव्यावहारिक है। पहचान सुनिश्चित करने पर चुनाव आयोग के जोर का सबसे तीखा विरोध हो रहा है। पहले कुछ तथ्य पर बात करें। 1 जनवरी, 2003 की सूची में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 96 लाख थी। वर्तमान में यह संख्या 7 करोड़ 89 लाख है। तो लगभग 2 करोड़ 93 लाख मतदाताओं को ही पहचान सुनिश्चित करनी होगी। जिन मतदाताओं के नाम 2003 में है उसके अलावा जिनका नाम आया उनको ही जन्मतिथि, जन्म स्थान आदि साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे।

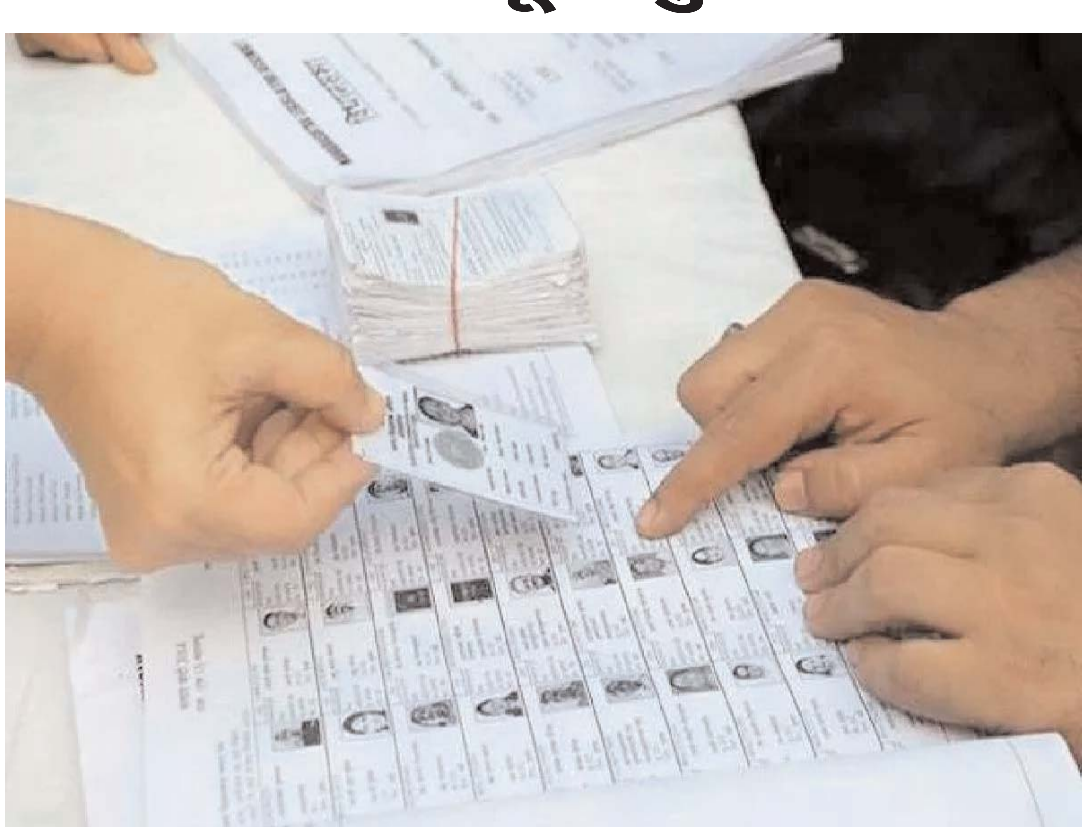

उनमें भी माता-पिता का नाम 2003 मतदाता सूची में है तो माता-पिता की पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। केवल 2003 वाली मतदाता सूची के उस हिस्से की कॉपी बीएलओ को देनी होगी जिसमें उनके माता-पिता का नाम लिखा है। जिनके नाम 2003 में हैं उन्हें केवल उसकी फोटो कॉपी बीएलओ को फॉर्म जमा करते समय देनी है जिसमें उनका नाम है। क्या 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले के पास अगर जन्मतिथि तथा जन्म स्थान साबित करने के प्रमाण नहीं हो तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा?

इसकी आशंका है। पर आयोग का कहना है कि दस्तावेजविहीन व्यक्ति की भारतीय पहचान को सुनिश्चित करने का काम क्षेत्र के एसडीम करेंगे और उनके कागजात का पता लगाने के लिए वालंटियर नियुक्त किए गए हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने यह डरावनी जानकारी दी है कि पुनरीक्षण में ऐसे विदेशी नागरिक मिले जो मतदाता बन चुके हैं। उनकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी जा रही है और नागरिकता सुनिश्चित होने के बाद ही तय होगा कि वे मतदाता रहेंगे या नहीं। राजनीतिक दलों ने इस पर भी तूफान खड़ा कर दिया। निस्संदेह, आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवाना आसान नहीं होता। इसलिए चिंता का विषय है कि यह हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार के भारी मुसलमान जनसंख्या वाले चार सीमांचल जिलों में आधार कार्ड के आंकड़े हैरत में डालते हैं।

बिहार में औसत आधार कार्ड आबादी के 94 फीसद है। किशनगंज में 68 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और आधार सैचुरेशन 126 प्रतिशत है, कटिहार (44%) में 123त्न, अररिया (43%) में 123त्न, और पूर्णिया (38%) में 121त्न आधार सैचुरेशन है। आबादी से अधिक आधार कार्ड कैसे बने हुए हैं? पिछले वर्ष अररिया में एक बंगलादेशी घुसपैठियों पकड़ा गया जिसके पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना से बना आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई केवल असम और बंगाल में नहीं बिहार के इन सीमांचल जिलों में भी रही है। क्या विरोधियों के दबाव में उन सबकी जांच नहीं होनी चाहिए? संविधान की धारा 326 चुनाव आयोग को भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में अंकित करने का अधिकार देता है। हालांकि नागरिकता की पहचान चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए उसने गृह मंत्रालय को मामला स्थानांतरित किया है।

विरोधी चाहे इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को परोक्ष रूप से लागू करना माने या कुछ और किंतु भारतीय नागरिकों तक ही मतदान की व्यवस्था और पूरी मतदान प्रणाली की शुचिता तथा भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सतर्कता आवश्यक है। एक बार मतदाता सूची का प्रारूप आ जाने दीजिए और देखिए कि कितने लोग पात्र लोग इससे वंचित होते हैं। अगर संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जहां एक भी पात्र नागरिक सूची में स्थान पाने से वंचित नहीं हो वही एक भी अपात्र उसमें शामिल नहीं हो यह भी आयोग, राजनीतिक दलों, प्रशासन और हम सबका दायित्व है।

(लेख में विचार निजी हैं)

ट्रंप प्रशासन की टैरिफ युद्ध

प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया के लगभग समस्त देशों के साथ ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ युद्ध की घोषणा कर दी गई है।

अमेरिका में विभिन्न देशों से होने वाले आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर एवं टैरिफ की दरों में बार-बार परिवर्तन कर तथा इन टैरिफ की दरों को लागू करने की तिथि में परिवर्तन कर ट्रंप प्रशासन टैरिफ युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, इस संबंध में अब स्पष्टता का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है।

ट्रंप द्वारा कई बार घोषणा की गई है कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता शीघ्र ही संपन्न किया जा रहा है। अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में गया था तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक वहां रहा एवं ऐसा कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय समझौते के अंतिम रूप को अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु अभी तक अमेरिका द्वारा अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा नहीं की जा रही है।

हालांकि, इस बीच अमेरिका द्वारा कई देशों के विरुद्ध टैरिफ की दरों को बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से जापान एवं दक्षिणी कोरिया से अमेरिका को आयात होने वाली वस्तुओं पर 1 अगस्त, 2025 से 25 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाएगा। इसी प्रकार, 12 अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर भी टैरिफ की बढ़ी हुई नई दरें लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। पूर्व में अमेरिका द्वारा चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी-भरकम टैरिफ की घोषणा की गई थी। चीन ने भी अमेरिका से होने वाली आयातित वस्तुओं पर लगभग उसी दर पर टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी थी। चीन ने विभिन्न देशों को दुर्लभ खनिज पदाथरे (रेयर अर्थ मिनरल) के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

अमेरिका में चीन के इस निर्णय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था जिसके दबाव में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता करते हुए चीन से आयात होने वाली विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ की दरों को तुरंत कम कर दिया। अमेरिका द्वारा इसी प्रकार का एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ भी संपन्न किया जा चुका है।

पूर्व में, ट्रंप प्रशासन ने 90 दिवस की अवधि में 90 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की बात कही थी तथा 90 दिवस की समयावधि 9 जुलाई को समाप्त होने के पश्चात भी केवल दो देशों ब्रिटेन एवं चीन के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता संपन्न हो सका है। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है परंतु इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

द्विपक्षीय समझौते के लिए शेष देशों पर दबाव बनाने की दृष्टि से ही इन देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर टैरिफ की दरों को एक बार पुनः बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, और इन बढ़ी हुई दरों को 1 अगस्त, 2025 से लागू करने की योजना बनाई गई है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा छेड़े गए इस टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने वैश्विक मंच पर न तो अमेरिका के टैरिफ की दरों में वृद्धि संबंधी निर्णयों की आलोचना की है, और न ही भारत में अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। बल्कि, भारत ने तो अमेरिका से आयात होने वाली कुछ विशेष वस्तुओं पर टैरिफ को कम कर दिया है।

दरअसल, भारत इस समय विकास के उस चक्र में पहुंच गया है, जहां पर भारत को अपना पूरा ध्यान आर्थिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को यदि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है, तो आगे आने वाले लगभग 20 वर्षों तक लगातार लगभग 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत अपने आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता दिखाई दे रहा है। भारत के रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रय प्रतिशतशील है। हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद एवं टोबैगो जैसे देशों की यात्रा इस उद्देश्य से संपन्न की है ताकि दुर्लभ खनिज पदाथरे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इन देशों में दुर्लभ खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत में 140 करोड़ नागरिकों का विशाल बाजार उपलब्ध है, जिसे अमेरिका एवं चीन सहित विश्व का कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यदि अमेरिका एवं चीन भारत के साथ अपने संबंधों को किसी भी कारण से बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो लंबी अवधि में इसका नुकसान इन्हीं का है।

सोहराय, पटचित्र और पटुआ कला के कलाकारों ने आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति से मुलाकात की

पीआईबी।

कलाकारों के एक समूह ने आज (24 जुलाई, 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ कला के 29 कलाकार 14 से 24 जुलाई, 2025 तक राष्ट्रपति भवन में रहे। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कलाकार राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव 2025 - 'आवासीय कलाकार कार्यक्रम' के दूसरे संस्करण में भाग ले रहे थे।

कलाकारों का आवासीय कार्यक्रम 'कला उत्सव' भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। यह सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में जीवंत कला परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पुनः पुष्टि करता है। इस कला उत्सव ने पीढ़ियों से कला के विविध रूपों को जारी रखने वाले लोक, आदिवासी और पारंपरिक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रपति ने कलाकारों द्वारा उनके आवासीय कार्यक्रम के दौरान बनाई गई कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक कला रूपों में उनके योगदान की सराहना की और उनके भावी कलात्मक प्रयासों में सफलता की कामना की।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी

पीआईबी

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम में उपयोग हेतु पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना चार कार्यक्षेत्रों, अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफ ायती आवास (एएचपी), इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋ ण-आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

सीएलएसएस वर्टिकल के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रति घर ?2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई। एमआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2021 को तथा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस 31.03.2022 को समाप्त हुआ। इस वर्टिकल को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को आवेदन प्रस्तुत किया गया। उचित जांच के बाद, सभी पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 25,04,220 लाभार्थियों को कुल ?58,885 करोड़ की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है। इसके अंतर्गत, देश भर के शहरी क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने और किराए पर देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार कार्यक्षेत्रों, अर्थात् लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान।

प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर घटने पर संगम के एक क्षेत्र का हवाई दृश्य।

जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में मैनेजमेंट, परचेज व मेस कमेटी की बैठक में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष

राजनांदगांव - जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ के पुस्तकालय कक्ष में बुधवार 23 जुलाई को सुबह 11.30 बजे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय परचेज कमेटी और जिला स्तरीय मेस कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाघे, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता सिन्हा, बीईओ श्रीमती वीरेन्द्र कौर गरचा, सीएमएचओ डॉ. नेतराम नवरत्न, खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ श्री सोनकले, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश यादव, केवी डोंगरगढ़ के प्राचार्य एसआर कुजुर, पालक प्रतिनिधि श्रीमती सरला साहू और त्रिलोक चौरे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

विद्यालय की ओर से प्राचार्य संजय कुमार मंडल, वरिष्ठ शिक्षक ओपी चौरसिया, एसके बिसेन, स्नेह अग्रवाल, एसके वर्मा, अनिल कुमार पॉल, जानकी उइके, अर्चना, उमा धुर्वे सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

प्राचार्य श्री मंडल ने अतिथियों को गमला भेंटकर स्वागत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक, खेलकूद और सह-शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। इसके पश्चात वरिष्ठ शिक्षक ओपी चौरसिया ने विद्यालय की प्रमुख आवश्यकताओं पर बिंदुवार प्रकाश डाला। इनमें ओवरहेड टैंक निर्माण, बधियाटोला से विद्यालय तक सड़क चौड़ीकरण,विद्यालय परिसर में सड़क स निर्माण और विभिन्न स्किल ज्ञ विषयों के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण शामिल थे।

संयुक्त कलेक्टर हितेश्वरी बाघे ने विद्यालय की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हर संभव नि सहयोग का भरोसा दिया। बैठक नि में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और क अधिकारियों ने भी अपने-अपने स विभाग की ओर से सहयोग देने की सहमति दी।

भारत में पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार

ईसीएएच : टीकाकरण, एएमआर जागरूकता और पशु चिकित्सा सुधारों की प्रगति की समीक्षा

लोकशक्ति

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के तत्वावधान में आज नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) की 9वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने की और उपाध्यक्षता, डीएएचडी सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने की। पीएसए कार्यालय, आईसीएमआर, सीडीएससीओ, डीबीटी, आयुष मंत्रालय और अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रमुख हितधारकों ने भारत में पशु स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रो. अजय कुमार सूद ने विभाग के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और पशुपालकों के बीच खुरपका-मुँहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर

विशेषकर मीडिया अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया। विभाग ने देश भर में पशु स्वास्थ्य प्रशासन को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से प्रमुख नियामक सुधारों और वर्तमान में चल रही कार्यक्रम संबंधी पहलों पर भी जानकारी दी। इन उपायों में पशु चिकित्सा दवाओं, टीकों, जैविक उत्पादों और आहार योजकों से संबंधित नियमों को सरल बनाना, साथ ही उच्च-गुणवत्ता वाले पशु स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुँच में सुधार करना शामिल था।

पशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनानाः अब तक हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत खुरपका-मुँहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक, एफएमडी वैक्सीन की 124.10 करोड़ खुराकें, पीपीआर वैक्सीन की 28.89 करोड़ खुराकें, ब्रुसेलोसिस वैक्सीन की 4.77 करोड़ खुराकें और सीएसएफ वैक्सीन की 0.88 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत पशुधन एप्लिकेशन के माध्यम से पशु टीकाकरण को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जा रहा है। एफएमडी उन्मूलन के लिए, विभाग नौ राज्यों में एफएमडी-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (एवीआईएन) के माध्यम से वैक्सीन कोल्ड चेन की वास्तविक समय निगरानी के लिए पायलट प्रयास शुरू किए हैं। राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत उपयोग किए जाने वाले सभी टीके स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित होते हैं, जिससे भारत को पशु टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है। भारत अन्य देशों को भी टीकों का निर्यात करता है, जो आत्मनिर्भर भारत और पशु स्वास्थ्य में वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, भारत के पहले अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (ई डी एफ सी) को 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू ओ ए एच) द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स (आरवीसी) केंद्र एवं महाविद्यालय में स्थित यह अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन, निर्धारित जैव सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के पूर्ण अनुपालन में भारतीय खेल घोड़ों की वैश्विक आवाजाही का मार्ग प्रशस्त करता है। पोल्ट्री क्षेत्र में, विभाग द्वारा 44 अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) कम्पार्टमेंट को मंजूरी दी गई है, जिससे निर्यात के लिए तैयार जैव सुरक्षा उत्पादन प्रणालियों को बनाए रखने की भारत की क्षमता को बल मिलता है।

इसके अलावा, डीएएचडी की सहायता से, आई सी ए आर- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल को हाल ही में डब्ल्यू ओ ए एच और एफएओ द्वारा ए श्रेणी रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी (आर एच एफ) के रूप में मान्यता दी गई है।

दूरसंचार सेवा में सुधार के लिए उठाए गए कदम

पीआईबी।

देश के व्यावसायिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और वंचित गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने कई परियोजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन सरकारी वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

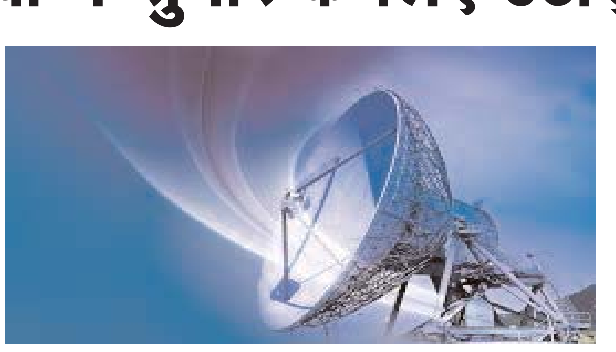

देश में ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। जून 2025 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,325 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची डिजिटल भारत निधि वेबसाइट (httpsÑ//usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 04.08.2023 को सरकार ने भारतनेट चरण-। और चरण-।। के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दे दी है, शेष 42,000 जीपी (लगभग) में नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। निर्माण चरण की पूर्णता के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्षों की समय-सीमा के साथ एबीपी के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद प्रचालन और रखरखाव आरंभ होगा।

देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, बीएसएनएल और देश के अन्य निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ साझेदारी में विभिन्न लक्षित योजनाएं/परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। 4जी परिपूर्णता और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत, जून 2025 तक देश में 21,748 मोबाइल टावर आरंभ किए जा चुके हैं।

अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को उच्च गति इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (2,312 किमी) के बीच तथा मुख्यभूमि (कोच्चि) तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह (1,869 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फ इबर केबल (ओएफ सी) परियोजनाएं बीएसएनएल के माध्यम से क्रमशः 10.08.2020 और 03.01.2024 को चालू की गई हैं। इन ऑप्टिकल फ इबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य उच्च गति डेटा/इंटरनेट सेवाओं को तेज़ी से शुरू करने में मदद की है।

Truhome FINANCE

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

मुख्य कार्यालय: लेवल-3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; **टेलीफोन:** 1800 102 4345; वेबसाइट: http://www.truhomefinance.in
पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवास टॉवर, पहली मंजिल, दरवाजा नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेनाम्पेट, चेन्नई-600018

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] **अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं एवं जमानतदार/ओं को सूचित किया जाता है कि ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर 30.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच ई-नीलामी में उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों से ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड को देय शेष राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जैसा कि तालिका में उल्लेख किया गया है। उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि तथा निरीक्षण की तिथि भी इस प्रकार दी गई है:

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधक का नाम	वसूली की राशि और मांग नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) एवं बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि व समय	संपर्क व्यक्ति का विवरण - AO एवं निपटान टीम
1. श्री हस्तीमल सोनी, पुत्र - श्री सांगीलाल सोनी (उधार लेने वाला) 2.श्रीमती संतोषी सोनी, पत्नी - श्री हस्तीमल सोनी (सह-उधारकर्ता) पता - वार्ड क्रमांक 05, पंडित दिनदयाल उपाध्याय वार्ड, भखारा, धमतरी, छ.ग.- 493770 ऋण खाता संख्या SLPHRAIP0000418 कब्जे की तारीख और समय: 27/05/2025 एवं सांकेतिक कब्ज़ा भार ज्ञात: अज्ञात	मांग नोटिस की तिथि: 11.03.2025 रु. 64,57,780/- 10/03/2025 तक साथ ही अतिरिक्त ब्याज और लागत शुल्क।	रु. 65,00,000/- (पैंसठ लाख रुपये मात्र) बोली वृद्धि: रु. 20,000/- और ऐसे गुणकों में बयाना राशि जमा (ईएमडी) (रु.): रु. 6,50,000/- (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 29/08/2025 समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक	30 अगस्त 2025 समय 11:00 बजे से 01.00 बजे तक	श्री रघुवीर सिंह - 8120000486 श्री संदीप सिंह - 9644676767 श्री अशफाक पटका - 9819415477 संपत्ति निरीक्षण दिनांक: 28/08/2025 प्रात: 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, आवासीय मकान जिसका प्लॉट नंबर 91 है, आबादी भूमि पर, खसरा नंबर 713/1 (खसरा नंबर 713 का पुराना हिस्सा) का हिस्सा, मोजा भखारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, वार्ड नंबर 05, पी.एच. नंबर 18 (पुराना पी.एच. नंबर 17), आर.आई.सी. भखारा (पुराना आर.आई.सी. कुरुद), तहसील भखारा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल 140.22 वर्ग मीटर, सीमा - पूर्व: अरुण गौड़ की भूमि और कुंज लाल साहू का मकान, पश्चिम: दयाराम की भूमि, उत्तर: गली, दक्षिण: दयाराम की भूमि

1) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की वेबसाइट देखें। 2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए गए खाते के विवरण में जमा करनी होगी: बैंक का नाम: एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा: बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई बैंक खाता संख्या: चालू खाता संख्या: 911020045677633 आईएफएससी कोड: यूटीआईबी0000230

स्थान: धमतरी छ.ग.
दिनांक 25-07-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी-
ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 हेतु अभ्यर्थियों और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिशा–निर्देश जारी

जांजगीर–चांपा। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जाने वाली आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के सफल, पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार प्रातः 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जैमर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर एक विशेष कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जो जैमर के संचालन हेतु प्रशिक्षित रहेगा। इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कार्य की निगरानी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।पुलिस बल द्वारा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी पुलिसकर्मी परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।सभी परीक्षार्थियों की हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और फ्रिस्किंग के माध्यम से जांच की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही की जाएगी।

साथ ही, प्रत्येक कक्ष में दीवार घड़ी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को समय की सही जानकारी मिल सके।

सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल हैं बीईओ मोहनलाल कौशिक

स्काउट-गाइड, शिक्षा और प्रशासन–हर क्षेत्र में अग्रणी योगदान

पामगढ़।

पामगढ़ विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मोहनलाल कौशिक एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा प्रशासन में, बल्कि स्काउट-गाइड के क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। उनका व्यक्तित्व सादगी, सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है।

जब वे शालाओं का निरीक्षण करते हैं, तो अन्य अधिकारियों की तरह कुर्सी पर अधिकार जताने की जगह, सामान्य शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर संवाद करना पसंद करते हैं। यही उनका मिलनसार और विनम्र स्वभाव उन्हें विकासखंड के शिक्षकों और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाता है।

स्काउट–गाइड में विशेष पहचान

मोहनलाल कौशिक पूर्व में जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) और जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) के रूप में दायित्वो का बेहतर रुप से निर्वहन किए है । उनके नेतृत्व में जांजगीर-चांपा जिले से 100 से अधिक स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

विशेष उल्लेखनीय यह है कि उनके अपने विद्यालय, शा. महामाया उ.मा.वि. पामगढ़ से ही 25 छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है। यह उनकी प्रेरक नेतृत्व क्षमता और स्काउट के प्रति सच्ची सेवा भावना का प्रमाण है।

राज्यपाल सम्मानित शिक्षक और तीन कालखंड की सेवा - श्री कौशिक को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्यपाल द्वारा ÷उत्कृष्ट शिक्षक÷ के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है।

बीईओ जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व के साथ-साथ वे आज भी अपने मूल शिक्षक धर्म को निभाते हुए शा. महामाया उ.मा.वि. पामगढ़ में प्रतिदिन तीन कालखंड पढ़ाते हैं, जो उनके कर्मठ और शिक्षार्थीप्रिय स्वभाव को दर्शाता है।

एक प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व

बीईओ मोहनलाल कौशिक ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो पद पर नहीं, कर्म और विचारों में महान होता है। उनका जीवन और कार्यशैली हर शिक्षक, अधिकारी और छात्र के लिए प्रेरणा है।

हरेली तिहार पर ग्राम खिसोरा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

प्रशासन और उद्योगों की साझेदारी में तैयार होगा ऑक्सी–ज़ोन,ग्रीन ज़ोन

जिले में पंचायत, सामजिक संगठनों, आम नागरिकों द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा वृक्षारोपण

जांजगीर–चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में प्रशासन और उद्योगों के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कराकर ऑक्सीजन जोन-ग्रीन जोन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में आज हरेली तिहार के अवसर पर अकलतरा विकासखंड के ग्राम खिसोरा में ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान 2.0 के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

किया गया। इस कार्यक्रम में एम वी के इंडस्ट्री, अमरताल के सहयोग से दो हजार से अधिक पौधे आम, अमरूद, आँवला, गुलमोहर सहित छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगों, नागरिकों, अधिकारी-कर्मचारी ने ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ संकल्प के साथ पौधरोपण किया।इस अवसर पर जिला खनि अधिकारी श्री अनिल साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री पवन कोसमा, उद्योग विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

जिले में पंचायतों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा विभिन्न स्थानों में सतत् रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा है। नागरिक पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम से जुड़कर ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ को एक जनांदोलन का स्वरूप दे रहे है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री महोबे के निर्देशन में यह अभियान जिलेभर में सतत् आगे बढ़ाया जा रहा है , वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, बेहतर पर्यावरण और प्राकृतिक सुंदरता का उपहार दिया जा सके।

करोड़ों रुपया धोखाधड़ी के आरोपी को जांजगीर पुलिस ने दबोचा

आरोपी द्वारा कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच दिखाकर लोगो से किया धोखाधड़ी

जांजगीर–चांपा /

करोड़ो रुपए धोखाधड़ी के आरोपी को जांजगीर पुलिस ने धर दबोचा है जिसके उपर आरोप है कि लोगों से कम समय में अधिक ब्याज देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई है । मामले का विवरण इस प्रकार है आरोपी नकुल साहू एवं उसके अन्य साथी के द्वारा लोगों को कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच दिखा कर किस्त किस्त में नगद एवं आरटीजीएस के माध्यम से कुल एक करोड़ 15 लाख रुपए ले लिया है। जमा किये पैसा को वापस मांगने पर आनाकानी कर रहा है। प्रार्थी परमेंद्र कुमार निवासी पुरानी बस्ती जांजगीर की रिपोर्ट पर दिनांक 22 जुलाई 2025 को थाना जांजगीर में अपराध कायम कर विवेचना लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर के नेतृत्व में आरोपी नकुल साहू को पकड़ा । धोखाधड़ी करने के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी के साथ मिलकर प्रार्थी व अन्य लोगों से एक करोड़ 15 लाख रुपए लेकर धोखाधडी करना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पांडे, उनि सत्यम चौहान, प्रधान आर. राजकुमार चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा।

परंपरागत रूप से मनाया गया हरेली त्यौहार

जांजगीर चांपा /

छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर स्थित श्री दूधाधारी मठ में हरेली का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर कृषि कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले नांगर, फावड़ा, गैंती, कुदारी, साबर, आदि विभिन्न कृषि यंत्रों की साफ सफाई की गई। जल से धोकर उन्हें पीढ़ा पर विराजित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। तथा श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद वितरित किया। गया महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि -जब से श्री दूधाधारी मठ की स्थापना हुई है तब से यहां हरेली का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाया जाता है इसे लोग नांगर तिहार के नाम से भी जानते हैं। कृषि कार्य में नांगर का बहुत महत्व है, पहले कृषि हल पर ही आधारित थी। वर्तमान में ट्रैक्टर आदि के प्रचलन से इसका उपयोग अब कम होने लगा है। उन्होंने कहा कि -हरेली के दिन लोग गौवंशियों की भी सेवा

करते हैं उन्हें निरोगी रखने के लिए अंडी की पत्तियां खिलाने की भी परंपरा ग्रामीण क्षेत्रों में है। लोग इसका निर्वाह करते हैं। उन्होंने हरेली पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर विशेष रूप से नागा जी महाराज, पुजारी रामावतार दास जी,रामदेव दास जी, शशांक जी, सुरेंद्र बैरागी, वैभव वैष्णव, भीष्मा, अंकित, नंदलाल फेकर, रतन साहू, राजा वैष्णव, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव सहित संत महात्मगन एवं विद्यार्थी गण काफी संख्या में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पर्व हरेली.......

जिले में मनाया गया हर्ष उल्लास और धूमधाम से... मनोज कालू अग्रवाल

जांजगीर चांम्पा द्यलोक पर्व हरेली जिले में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया । वहीं समाजसेवी एवं पूर्व एल्डरमैन मनोज कालू अग्रवाल ने हरेली की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए बताया कि इस अवसर पर किसानों ने हल व कृषि औजारों की पूजा की। पर्व के चलते आज खेती बाड़ी का काम पूरी तरह बंद रहा। गांव–गांव में नारियल जीत–हार

का खेल हुआ, वहीं बच्चों ने गेंड़ी का आनंद लिया। हरेली त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह था। सुबह से ही ग्रामीणों ने हल व अन्य कृषि औजारों को तालाब में ले जाकर धोया और आंगन में चौक बनाकर हल, पावड़ा, टांगी उन्नत कृषि यंत्र ट्रैक्टर, केज व्हील आदि की पूजा–अर्चना की। इस दौरान चीला, बोबरा और नारियल का भोग लगाया गया। पर्व को लेकर आज खेती किसानी का काम पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने नारियल के जीत हार की बाजी लगाई और नारियल फेंकने की स्पर्धा जमकर हुई, जिसके चलते नारियल की बिक्री बढ़ गई थी। इधर बच्चे व युवाओं ने गेंड़ी का भी खूब आनंद लिया। शहरी क्षेत्रों में भी हरेली त्यौहार मनाया गया। शहरों में जिनके घर हल व कृषि औजार नहीं है उन्होंने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर पर्व की परंपरा निभाई। सड़कों में नारियल की हार जीत खेलने वाले लोगों की टोली नगर में दिखी। सुबह से ही त्यौहार को लेकर बच्चे, युवा व बुजुर्गों में उत्साह था। एक दिन पहले शाम से ही लोगों ने त्यौहार की तैयारी कर ली थी।

प्रो. वीके सारस्वत बने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति, घनश्याम तिवारी ने दी शुभकामनाएँ

बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में प्रोफेसर रहे डॉ. वीके सारस्वत को पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर का नया कुलपति बनाया गया है। यह नियुक्ति राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9(1) के तहत की गई है। प्रो. सारस्वत शिक्षा के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उनके नाम पर 38 से अधिक शोध पत्र दर्ज हैं और वे कई राष्ट्रीय शैक्षणिक परियोजनाओं का संचालन कर चुके हैं। IET आगरा के निदेशक के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया है।

उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक और तकनीकी सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराता है। प्रो. सारस्वत के नेतृत्व में विश्वविद्यालय को शोध, नवाचार और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मजबूती मिलने की संभावना है। प्रदेश संयोजक – पैक्स प्रकोष्ठ,

सहकार भारती छत्तीसगढ़ घनश्याम तिवारी ने प्रो. सारस्वत को फोन पर बधाई दी और बिलासा माता की पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री तिवारी ने कहा कि एक अनुभवी शिक्षाविद के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय नई ऊँचाइयों को छूएगा।

विश्वविद्यालय परिवार, शिक्षकों और विद्यार्थियों में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर खासा उत्साह है। सभी को विश्वास है कि प्रो. सारस्वत की दूरदर्शिता से विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करेगा।

भारतीय मजदूर संघ का 70 वां स्थापना दिवस मनाया गया.......

जांजगीर–चाम्पा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ, चाम्पा एवं भारतीय मजदूर संघ, जिला जांजगीर के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय मंत्री एवं जिला मजदूर संघ की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती गीता सोनी उपस्थित रहीं। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की ÷शून्य से शिखर तक÷ की संघर्षपूर्ण यात्रा को याद करते हुए श्रमिकों की एकता और संगठन की शक्ति को रेखांकित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ, चाम्पा के शाखा अध्यक्ष अजय कुमार ने की। इस अवसर पर शाखा सचिव धर्मेन्द्र गिरी, उपाध्यक्ष असित हलदार, कार्यालय सचिव ज्योतिष कुमार, सतपाल कंवर, त्रिलोकचंद मिरी, जिला मजदूर संघ कार्यकारिणी सदस्य गजानन बनारे और शोभा यादव सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में संघ की रीति-नीति, श्रमिक कल्याण और सामाजिक योगदान पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ न केवल मजदूरों की आवाज है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में एक सशक्त भागीदार भी है। समापन पर ÷भारतीय मजदूर संघ अमर रहे! अमर रहे!÷ के नारों से कार्यक्रम गूंज उठा।

विभिन्न अग्र संस्थाओं के स्थान पर एक नव–विचारित, संविधान आधारित अग्र महासंघ या और कोई नाम के गठन संबंधी एक परामर्श : जगदीश प्रसाद अग्रवाल

जांजगीर चांपा - छत्तीसगढ़ प्रांतीय चेयरमैन जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान समय में विभिन्न समानान्तर अग्र संस्थाएं अपने- अपने स्तर पर सेवा, संगठन एवं सहयोग का कार्य कर रही हैं। जिन्हें सहमति / समन्वय के माध्यम से एक फोरम, फेडरेशन, यूनियन का स्वरूप प्रदान करने की चर्चा चल रही है।

इतिहास साक्षी है कि समान उद्देश्य हेतु कार्यरत अनेक समानांतर संगठनों के बीच परस्पर समझौते (Agreement) या समन्वय (Co-ordination) से गठित फ ोरम, फेडरेशन अथवा यूनियन जैसे मंच, कभी भी दीर्घकालीन एवं प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सके हैं। अतः एक परामर्श के रूप में यह विचार प्रस्तुत है कि - यदि हम वास्तव में एक संगठित, समन्वित एवं सशक्त विश्व / राष्ट्र व्यापी अग्र संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें मौजूदा संस्थाओं के समानांतर कोई मंच खड़ा करने के स्थान पर, उनकी संरचनाओं के स्थान पर एक नवीन, संविधान सम्मत, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी ÷अग्र महासंघ या और कोई नाम÷ का गठन करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमें

सर्वप्रथम एक वैचारिक एवं संवैधानिक मंच ÷श्री अग्रसेन संविधान महासभा÷ ङ्क का गठन करना चाहिए, जो न केवल भावी ÷अग्र महासंघ या और कोई नाम÷ के लिखित संविधान का निर्माण करेगा, बल्कि उसमें अग्र समाज के गोत्र, क्षेत्र, विस्तार आदि का निर्धारण करेगा। यह कोई साधारण पहल नहीं होगी, बल्कि यह संपूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन (Systemic Reform) की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा ङ्क जो ÷अग्रवालों के द्वारा, अग्रवालों के लिए, और अग्रवालों का÷ सच्चा प्रतिनिधि संगठन स्थापित करने की आधार-शिला रखेगा। निष्कर्षतः यह समन्वय नहीं, बल्कि संविधान आधारित पुनर्संरचना की प्रक्रिया है, जो भविष्य में हमारे समाज को संगठित शक्ति, एकीकृत नेतृत्व और साझा दृष्टिकोण प्रदान करेगी। उपरोक्त विचार, परामर्श एवं दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार मित्तल सहर्ष समर्थन करते हैंद्य प्रांतीय चेयरमैन जगदीश प्रसाद अग्रवाल बिलहा श्री अग्रसेन प्रचार समिति

छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ने अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन , विचार आप सभी के समक्ष सादर विचारार्थ संप्रेषित है।

इसकी प्रतिलिपि उन्होंने राजकुमार मित्तल, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन को अग्रेषित किया है।

खास खबर

स्वतंत्रता सह सद्भावना दौड़ 14 अगस्त को-

एजेंसी। 14 अगस्त को प्रातः 8 बजे सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जायेगा। इस दौड़ में सभी नागरिक, छात्र-छात्राएं, अधिकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। यह दौड़ घंटाघर चैक से प्रारंभ होकर निहारिका-सुभाष चैक बायां मुड़ते हुए विद्युत गृह स्कूल - बुधवारी बाजार चैक जैन मंदिर से- महाराणा प्रताप चैक से होते हुए पुनः घंटाघर स्थित ओपन थियेटर में समाप्त होगी।

राष्ट्रध्वज की गरिमा का रखे विशेष ध्यान:- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने कार्यालय में फहराये जाने वाले राष्ट्रध्वज की जांच पड़ताल कर लें। राष्ट्रध्वज कटे-फटे व छेद युक्त न हो, साफ-सुथरे हों तथा राष्ट्रध्वज सीधे फहराये जाएं। राष्ट्रध्वज की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाएं। फ्लेग कोड के प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो।

पशुधन विकास विभाग स्थायी समिति की बैठक 25 को

कोरबा जिला पंचायत कोरबा की पशुधन विकास विभाग स्थायी समिति की बैठक 25 जुलाई को दोपहर एक बजे कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें कोरबा में आयोजित की गई है।

आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने छात्राओं से आवेदन आमंत्रित

कोरबा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना कन्या जिला दुर्ग में संचालित है। जिसमें विज्ञान (गणित एवं जीव विज्ञान संकाय) तथा वाणिज्य विषय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर एव बी.एड. तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। योजना का यह उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में उल्लेखित विषयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए योजना विभाग द्वारा संचालित की गई है।

कोरबा जिला अंतर्गत इस योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक छात्राएँ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा जिला-कोरबा में आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी

कोरबा पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेष परीक्षा 30 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। जिसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा में सम्मलित हुए छात्र-छात्राओं का अंकों के आधार पर मैरिट सूची जारी किया गया है, जिसका अवलोकन जिले की वेबसाइट एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा के सूचना पटल में किया जा सकता है। इस संबंध में दावा आपत्ति 25 जुलाई के शाम 05 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा में जमा किया जा सकता है।

डीएमएफसे मिले कार्यों का टेंडर समय पर पूरा करें निर्माण एजेंसी : कलेक्टर

0 छुटे हुए हितग्राहियों का आधार अपडेट कराकर आयुष्मान और व्यवन्दन 15 दिन में बनाने दिए निर्देश

0 पुराने छात्रावासों में अधीक्षक आवास नहीं होने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

0 कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक

कोरबा

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टीएल के विभागवार लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि डीएमएफ अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का टेण्डर निर्माण एजेंसी समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सितंबर माह से प्रस्तावित कार्यों को प्रारंभ करने के दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पुराने छात्रावासों में जहाँ अधीक्षक आवास नहीं बने हैं, उन छात्रावासों की सूची उपलब्ध कराने के साथ ही आवास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने आयुष्मान और व्यवन्दन कार्ड के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जो हितग्राही आयुष्मान और व्यवन्दन कार्ड से वंचित है उन्हें लाभान्वित करने के लिए जनपद सीईओ के सहयोग से संबंधित क्षेत्र में शिविर लगाकर उनका कार्ड बनाया जाए। कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वंचित हितग्राहियों का अनिवार्य रूप से आयुष्मान और व्यवन्दन कार्ड बनाने के निर्देश नगर निगम, एसडीएम, जनपद को दिए। कलेक्टर ने योजना बनाकर शिविर लगाने और वंचित होने पर संबंधित के विषय में पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आधार अपडेशन में सहयोग नहीं करने वाले ऑपरेटरों की आइडी ब्लॉक करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने स्कूल एवं आंगनबाड़ी में संचालित रसोई में गैस का उपयोग करने और समय पर रिफलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्र में निरीक्षण करें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जनपद अन्तर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वर्ष 2020 के पूर्व स्वीकृत कार्यों में से स्कूल भवन एवं अन्य कार्य अधूरे हैं उसका परीक्षण करा लें। भवन के जर्जर हो जाने अथवा वसूली प्रकरण वाले मामले में प्रकरण दर्ज कर रिवाइज्ड स्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करें ताकि अधूरे भवन को पूर्ण कराया जा सके। कलेक्टर ने बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य विभागों अन्तर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ कटघोरा श्री कुमार निशांत एवं सभी अधिकारी उपस्थित थे।

(कोरबा) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा में आयोजित होगा नि:शुल्क कैंसर जॉच एव परामर्श शिविर

कोरबा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कोरबा एवं बालको मेडिकल सेंटर, नयारायपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक सामु.स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा में निःशुल्क कैसर जॉच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जायेगा। इस शिविर में विश्व स्तरीय कैंसर विशषज्ञों द्वारा जॉच एवं परामर्श दिया जावेगा। तथा मेमाग्राफी मशीन, मुख कैसर परीक्षण (ब्रश साईटोलॉजी), स्त्री कैंसर रोग संबंधी परीक्षण (पेप स्मीयर) सेवायें उपलब्ध होंगी।

मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस.एन.केशरी ने बताया कि किसी भी महिला या पुरूष में लक्षण दिख रहे हैं जैसे स्तन में गॉठ, मुंह में अल्सर या गले में गॉठ, मल या मूत्र विसर्जन की आदतों में परिवर्तन, थकान व वजन में अनापेक्षित बदलाव, लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ, खून की कमी, सिकलसेल एनीमिया, थैलेसिमिया, रक्त संबंधित बिमारियां, निगलने में कठिनाई या आवाज में बदलाव, रक्तस्त्राव या चोट न भरना, रजोनिवृत्ति के बाद रक्त जाना या असामान्य मासिक धर्म होना ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।

सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष आईटी कॉलेज कोरबा के 10-10 विद्यार्थियों को दें रोजगार : कलेक्टर

o संस्था के संचालन हेतु बालको को इस वित्तीय वर्ष 2 करोड़ की सहायता व सभी प्रतिष्ठानों को प्रत्यक्ष भागीदारी निभाने के दिए निर्देश

o आईटी कॉलेज कोरबा के सुचारू व निर्बाध संचालन हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की हुई बैठक

o संस्थान की चुनौतियाँ, संचालन से जुड़ी आवश्यकताओं और भविष्य की कार्ययोजना पर हुई चर्चा

कोरबा । कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरबा के सुचारू एवं निर्बाध संचालन के लिए जिले के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज बंजारे सहित एनटीपीसी, सीएसईबी, बालको, एसईसीएल कोरबा एवं अडानी इंडस्ट्रीज एवं आईटी कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।बैठक में आईटी कोरबा की वर्तमान वित्तीय स्थिति, संस्थान की चुनौतियाँ, संचालन से जुड़ी आवश्यकताओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि संस्थान गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन, संचालन व्यय एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने संस्थान को इस संकट से उबारने हेतु सभी औद्योगिक उपक्रमों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। जिससे कॉलेज का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

कलेक्टर श्री वसंत ने बालको को चालू वित्तीय वर्ष में संस्था को न्यूनतम 2 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके लिए बालको बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव रखकर कर स्वीकृति लेने के लिए कहा। साथ ही अन्य सभी औद्योगिक संस्थानों को भी आईटी कोरबा के संचालन में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई औद्योगिक संस्थान आईटी कॉलेज के संचालन में रूचि रखता है, तो वह औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर सकता है। साथ ही कॉलेज के भविष्य के संचालन हेतु उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप रोजगारोन्मुखी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्लेसमेंट के माध्यम से प्रतिवर्ष आईटी कॉलेज कोरबा से अध्ययनरत 10-10 विद्यार्थियों को अपने यहां नियोजित करने के निर्देश दिए। इस हेतु इंडस्ट्रीज को अपने-अपने बोर्ड की बैठक में एजेंडा शामिल कर इस सम्बंध में सकारात्मक निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया।

स्पॉन्सरशिप योजना से संवर रहा बच्चों का भविष्य

कोरबा जिलों में बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने हेतु किशोर न्याय अधिनियम तथा आदर्श नियम के प्रावधान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मिशन वात्सल्य (एकीकृत बाल संरक्षण) योजना संचालित है। योजना अंतर्गत विधि से संघर्षरत एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ के माध्यम से सभी जिलों में संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध है। जिसके अंतर्गत जिले में किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है। जिले में निवासरत ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता नहीं है। जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण तथा पालन पोषण, शिक्षा हेतु विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन बच्चों हेतु शासन की स्पॉन्सरशिपयोजना अंतर्गत चार हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि उन बच्चों को बेहतर देखरेख एवं संरक्षण तथा पालन पोषण, शिक्षा प्राप्त हो सके।

इस उद्देश्य के परिपालन में कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति जिला कोरबा श्री अजीत वसंत के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणु प्रकाश, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र देव सिंह के मार्गदर्शन में बालक कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्पॉन्सरशिप कमेटी के माध्यम से अब तक 122 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

जिला असंगठित विद्युत कामगार कल्याण समिति की महापौर संजू देवी राजपूत बनी संरक्षक

कोरबा लोकशक्ति।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत विद्युत कामगारों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए सक्रिय जिला असंगठित विद्युत कामगार कल्याण समिति की नगर निगम कोरबा महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत समिति की संरक्षक नियुक्त हुई हैं। एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ब्रह्म वाटिका ब्राह्मण समाज भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

उक्त भव्य सम्मान समारोह के दौरान महापौर का समिति के पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से पुष्पगुच्छ, श्रीफल, शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महापौर द्वारा संरक्षक के रूप में जुड़ने से असंगठित विद्युत कामगारों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के प्रयासों को नई दिशा और गति मिलेगी। कार्यक्रम में समिति के जिला अध्यक्ष राजेश दुबे, उपाध्यक्ष तिलक ध्रुव, सचिव मुकेश सिंह राजपूत, सह सचिव मनोज रत्न परखी, कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, विधि सलाहकार निखिल शर्मा एवं महेश शुक्ला, मार्गदर्शक के रूप में पूर्व पार्षद परवीन रतन परखी, मीडिया प्रभारी कमल कुमार तिवारी, समिति के सदस्य शिव यादव, कृष्ण महाराज, विशेश्वर राठौर, लेखराम पटेल, समीर महंत, मुन्ना, हीरा साहू, भगवत प्रसाद, अंगद यादव, प्रेम पांडे, करण पटेल, दिनेश तिवारी, प्रदीप द्विवेदी, शगुन महंत, राजकुमार राठौर सहित संगठन के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन करमजीत भारद्वाज ने किया।

बालको ने 'क्वालिटी संकल्प' से उत्पाद की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को दिया बढ़ावा

कोरबा-बालकोनगर वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने 'क्वालिटी संकल्प' नामक एक गुणवत्ता परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। यह कंपनी की 'शून्य दोष' प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और विविध उत्पाद श्रेणियों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मासिक आयोजन में 300 से अधिक कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों ने भाग लिया, जिससे संयंत्र में गुणवत्ता के प्रति साझी जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

बालको में गुणवत्ता हर उत्पादन चरण का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। कच्चे माल के चयन से लेकर अंतिम उत्पाद निरीक्षण तक सभी चरणों में गुणवत्ता जांच की जाती है। कोक, पिच, एल्युमिना और एल्यूमिनियम फ्लोराइड जैसे कच्चे माल की रासायनिक और भौतिक मापदंडों, कार्बन और सल्फर की मात्रा एवं कण आकार की सूक्ष्मता से जांच की जाती है ताकि स्मेल्टिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाई जा सके।

पॉटलाइन में धातु पिघलाने की प्रक्रिया के दौरान क्रायोलाइट अनुपात को नियंत्रित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रभावशीलता बढ़े। उसके बाद उत्पन्न पिघले हुए एल्यूमिनियम की शुद्धता जांच की जाती है और फिर उसे कास्ट किया जाता है। कास्टिंग के बाद मिश्र धातु तत्वों के समान वितरण के उपरांत धातु की संरचनात्मक जांच की जाती है। इन सभी चरण पर की गई गुणवत्ता जांच न केवल उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सस्टेनेबलव संचालन में भी योगदान देती है।

क्वालिटी संकल्प' को 'स्टैंडर्ड वर्क = क्वालिटी वर्क' की थीम के अंतर्गत शुरू की गई है, जो यह दर्शाता है कि मानकीकृत प्रक्रियाएं ही उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने की कुंजी होती हैं। यह मासिक पहल व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देकर, संगठन भर में गुणवत्ता से जुड़े कार्यों की शिक्षा, निगरानी और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है। इससे बालको को धातु उद्योग में एक उच्च गुणवत्ता वाला एल्युमिनियम निर्माता बनने में मदद मिलेगी।

गरिमामय एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को सौपीं जिम्मेदारी

लोकशक्ति कोरबा

कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने हेतु बैठक लेकर सभी विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कर्तव्यों का गम्भीरता पूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए है। आजादी के पर्व के दौरान 15 अगस्त को शासकीय कार्यालयों व मुख्य समारोह में राष्ट्रध्वज संहिता का पालन करते हुए पूरी गरिमा और सम्मान के साथ ध्वज फहराया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह कोरबा नगरीय क्षेत्र के फुटबाल मैदान सीएसईबी कोरबा पूर्व में आयोजित होगा। 15 अगस्त को समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय संस्थाओं में प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। मुख्य समारोह में ध्वजारोहण एवं सलामी कार्यक्रम के प्रभारी पुलिस अधीक्षक होंगे। जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल पुरूष व महिला, छत्तीसगढ़ नगर सेना पुरूष व महिला दल भाग लेंगे। स्वतंत्रता दिवस आयोजन का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त कोप्रातः 9 बजे किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी व परियोजना अधिकारी राजीव गांधी शिक्षा मिशन होंगे।

फुटबाल मैदान सीएसईबी कोरबा पूर्व की ग्राउण्ड व्यवस्था, साफ-सफाई, शामियाना, माईक व्यवस्था, कुर्सी, सोफा सेट, गमले, व्हीआईपी हेतु पेय जल व्यवस्था, ध्वजारोहण, मंच की साज सज्जा, गुब्बारे झण्डे आदि की व्यवस्था नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा किया जायेगा।झंडे हेतु खम्भे एवं आवागमन हेतु बेरीकेडिंग लगाने लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। बांस-बल्ली हेतु वन विभाग कोरबा को जिम्मेदारी दी गई। विद्युत संबंधी व्यवस्था की देखरेख अनुविभागीय अधिकारी विद्युत/यांत्रिकी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम स्थल में निर्बाध गति से विद्युत व्यवस्था का संचालन कार्यपालन अभियंता वितरण सीएसईबी शहर संभाग कोरबा की होगी।

समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि एवं जन समुदाय की बैठक सम्बंधित व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा एवं तहसीलदार कोरबा को सौपी गई है। राष्ट्रगान की प्रस्तुति पुलिस बैंड द्वारा दी जाएगी। निमंत्रण पत्र छपाई की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा एवं वितरण की व्यवस्था प्रोटोकॉल अधिकारी कोरबा द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम एवं रिहर्सल में आवश्यकता अनुसार वाहन व्यवस्था प्रोटोकॉल अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जाएगी। मार्च पास्ट एवं रिहर्सल में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों के स्वल्पाहार की व्यवस्था महाप्रबंधक एनटीपीसी एवं मुख्य समारोह के दिवस स्वल्पाहार की व्यवस्था आयुक्त नगर पालिका निगम द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले अन्य अतिथियों हेतु चिकित्सा व्यवस्था के प्रभारी सीएमएचओ होंगे। समारोह स्थल पर आवश्यक डॉक्टर, स्टाफ एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र छपवाने की व्यवस्था जिला पंचायत कोरबा द्वारा किया जाएगा। सभी विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 अधिकारी/ कर्मचारियों को 15 अगस्त समारोह के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की व्यवस्था सीईओ बाल्को, मुख्य अभियंता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल उत्पादन कोरबा पश्चिम एवं महाप्रबंधक एसईसीएल द्वारा किया जाएगा। पुरस्कार वितरण की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला पंचायत कोरबा को सौपीं गई है।

कटघोरा की चैपाटी और पुष्पवाटिका निर्माण में भारी घोटाला, डीएमएफफंड की खुली लूट

कोरबा, नगर पालिका क्षेत्र में हाल ही में लोकार्पित चैपाटी और पुष्पवाटिका अब भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का प्रतीक बनती जा रही हैं। 10 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन किए गए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, चैपाटी पर 19.41 लाख रुपये और पुष्पवाटिका पर 62.69 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। लेकिन जब इन स्थानों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया तो बेंच तक नहीं, स्ट्रीट लाइट अधूरी, फव्वारे गायब और निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। पुष्पवाटिका की हालत और भी खराब है कृ पौधों के नाम पर गड्ढे, मिट्टी और कूड़ा नजर आता है।

खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए क्डथ् फंड को अफसरों और ठेकेदारों ने लूट का जरिया बना लिया है। आरोप हैं कि निर्माण कार्य में 30ः से 50ः तक कमीशन की डील तय हुई, जिसमें अफसरों से लेकर ठेकेदारों और कार्यालय तक पैसा बांटा गया। दावा किया गया था कि चैपाटी में हर सुविधा होगी कृ बैठने की अच्छी व्यवस्था, सुंदर टाइल्स, जल फव्वारे और रोशनी की पूरी व्यवस्था। मगर सच्चाई ये है कि स्टील के कुछ अधूरे स्ट्रक्चर और अधपकी टाइल्स के अलावा वहां कुछ नहीं है।

मुख्यमंत्री ने दी जशपुर जिले को 11 करोड़ 52 लाख रुपए की सौगात

0 तीन स्थानों पर होंगे उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण......

जशपुरनगर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के तीन प्रमुख नदी-नालों में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए कुल 11 करोड़ 52 लाख 43 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण अंचल की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और वर्षा ऋतु में भी अब नागरिकों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी।

तीन प्रमुख स्थलों पर होगा पुल निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा जशपुर जिले के बोडोकछार से चटकपुर मार्ग पर स्थित चंपाझरिया नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 46 लाख 58 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ता है और पुल निर्माण से वर्षा के दिनों में बहाव से कटने वाली सड़क की समस्या स्थायी रूप से दूर होगी।जिले के भालूमुंडा-खजूरघाट मार्ग पर स्थित कोकिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 3 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को पूरे साल निर्बाध रूप से आवाजाही की सुविधा मिल सकेगी।डूमरबहार से तमता मार्ग पर शेखरपुर के पास गुढ़ा नाला पर बनाया जाएगा। यहाँ 3 करोड़ 73 लाख 85 हजार रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी सुगमता से पहुंच सकेंगी।

हॉस्टल वार्डन की बेरहमी, छात्रों को रॉड से बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे

0 जगदलपुर के नवोदय विद्यालय का है मामला

0 सात छात्रों की बेरहमी से पिटाई, परिजन आक्रोशित

0 वार्डन सौरभ अवस्थी पर लगा दरिंदगी का आरोप

0 बर्दाश्त नहीं की जाएगी बच्चों से क्रूरता : बघेल

जगदलपुर, । हर माता पिता की ख्वाहिश रहते है कि उनके बेटे बेटियों को नवोदयविद्यालय में दाखिला मिले, मगर जगदलपुर के नवोदय विद्यालय जो कारनामे हो रहे हैं, उसे देख सुनकर हर माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां हॉस्टल वार्डन ने मासूम छात्रों के साथ जो दरिंदगी की है, उसे देख पत्थर दिल भी रोने लग जाएंगे। दरअसल नवोदय विद्यालय जगदलपुर एक बार फिर विवादों में आ गया है। ताजा मामला स्कूल के हॉस्टल वार्डन द्वारा सात छात्रों की बेरहमी से पिटाई से जुड़ा है। इस घटना से अभिभावकों और समाज में आक्रोश भर दिया है।परिजनों के अनुसार यह घटना सोमवार रात की है। हॉस्टल की बिजली अचानक गुल हो गई। अंधेरा होते ही कुछ छात्र अपने कमरे में नाच-गाना करने लगे। तभी हॉस्टल वार्डन सौरभ अवस्थी वहां जा पहुंचे। वे बच्चों पर टूट पड़े। अवस्थी ने लोहे की रॉड से छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। छात्रों की पीठ, बांह, पैरों पर ताबड़तोड़ वार किए। बच्चे चीख पुकार मचाते रहे, रोते बिलखते रहे, मगर वार्डन अवस्थी ने तरस नहीं खाई। हमले में कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनके निशान अब भी उनके शरीर पर साफदेखे जा सकते हैं। घटना के अगले दिन घायल छात्रों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते हैं कि वार्डन द्वारा छात्रों के साथ ? सी अमानवीयता पहले भी कई बार की जा चुकी है। कुछ शिक्षक भी बच्चों पर जुल्म ढाते हैं। इस पूरी घटना की आधिकारिक पुष्टि स्कूल प्रबंधन द्वारा अब तक नहीं की गई है।

शार्ट न्यूज

जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनांतर्गत कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी

सुकमा, (आरएनएस)। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत जिले में कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। चयन परीक्षा में सम्मिलित सर्व संबंधित छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों को परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई दावा आपत्ति हो तो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सहायक आयुक्त कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। नियत समय और तिथि के पश्चात दावा आपत्ति अमान्य किया जाएगा।

कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग 28 को

सुकमा, (आरएनएस)। प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु मेरिट एवं द्वितीय प्रतीक्षा सूची से राज्य स्तरीय काउंसलिंग 28 जुलाई को होगा। छत्तीसगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की वर्गवार मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट एकलव्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपलोड कर दिया गया है। द्वितीय प्रतीक्षा सूची में दर्शित विद्यार्थीयों का काउंसलिंग, निर्धारित तिथि एवं समय में होगा। इसलिए वे सभी दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। मेरिट सूची में दर्शित विद्यार्थी के साथ एक अभिभावक, पालक को काउंसलिंग स्थल में प्रवेश की पात्रता होगी और निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीट के आधार पर संस्था आबंटित किया जाएगा।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सुकमा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर में स्थित प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ीयारी को काउंसिलिंग स्थल बनाया गया है, जहां काउंसिलिंग 28 जुलाई को समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इस दिन मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची के सभी वर्ग के बालक और बालिका प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के साथ काउंसिलिंग में उपस्थित हो सकते हैं।

दुर्ग) कीटनाशक पीकर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश

दुर्ग,। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक युवक ने कीटनाशक पीकर अपने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की जिसके बाद उसे फॉर आईटी तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है दरअसल रितेश सिंह की एक युवक से गहरी मित्रता और दोस्ती थी दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे इसी बीच उसके दोस्त ने रितेश सिंह के नाम पर एक गाड़ी फाइनेंस करवा लिए और कर फाइनेंस करा कर दोनों में यह तय हुआ कि फाइनेंस वाले ही रितेश सिंह के नाम पर हो लेकिन किस्त रितेश सिंह का दोस्त ही भरेगा लेकिन पिछले 6 महीना से रितेश सिंह का दोस्त किस्त नहीं भर रहा था जिसके कारण बैंक वाले रितेश सिंह को लगातार परेशान कर रहे थे जिससे तंग आकर रितेश सिंह ने आज कृषि उपज मंडी के पास कीटनाशक जहर लेकर पी लिया जिसकी सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी सभी ने मिलकर तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज किया जा रहा है इतना ही नहीं रितेश सिंह ने बाकायदा एक 07 पन्नों का नोट भी छोड़ा है जिसमें सारी बातें लिखी गई है फिलहाल दुर्ग पुलिस अब इस मामले पर विवेचना कर रही है।

हरेली तिहार : छत्तीसगढ़ की हरियाली, संस्कृति और सामाजिक एकता का उल्लास

धमतरी, संवाददाता

छत्तीसगढ़ की धरती पर जब सावन की पहली अमावस्या दस्तक देती है, तो प्रकृति के हर कोने में हरियाली की गूंज सुनाई देने लगती है। इसी उल्लास और जीवंतता का प्रतीक है 'हरेली तिहार', जो न केवल कृषि जीवन का उत्सव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की गहराई से जुड़ी संस्कृति, परंपरा और लोकचेतना की झलक भी है। पूरे छत्तीसगढ़ सहित धमतरी ज़िले में कल 24 जुलाई (गुरुवार) को हरेली तिहार उत्साह के साथ मनाया जाएगा । ग्रामीणों व किसानों ने खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा करेंगे । इस मौके लोग एक पेड़ माँ के नाम से भी लगायेंगे।धमतरी जिले में खासकर ग्रामीण इलाकों में यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है ।

हरेली: हरियाली का पर्व, आत्मा की ताजगी

'हरेली' शब्द स्वयं में ही हरियाली का संदेश समेटे है। यह त्यौहार केवल प्रकृति की पूजा नहीं है, बल्कि उस श्रम का उत्सव है जो किसान खेतों में दिन-रात पसीना बहाकर रचता है। हरेली एक प्रतीक है–धरा और मानव के बीच उस अटूट संबंध का, जो भूमि को माता और हल को भगवान का दर्जा देता है।

हरेली तिहार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में रचा-बसा पर्व है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह त्यौहार उस समय आता है, जब खेतों में बीज बो दिए जाते हैं और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी वर्षा की प्रार्थना करता है।

धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का मिलन

हरेली केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक परंपरा का जीवंत रूप है। इस दिन हल, गैंती, कुदाल जैसे कृषि औजारों की पूजा की जाती है। किसान इन्हें सजाकर धूप-दीप दिखाते हैं। यह कर्म न केवल प्रकृति और औजारों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि जीवन की बुनियादी विनम्रता को भी प्रकट करता है। गौरी-गौरा की पूजा, महिलाएं पारंपरिक गीतों और पकवानों के साथ करती हैं, जिसमें मातृशक्ति की पूजा और पारिवारिक समरसता की कामना समाहित होती है।

प्रकृति संरक्षण का लोक संदेश

हरेली तिहार केवल धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि यह पर्यावरण चेतना का भी प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा की गई 'एक पेड़ माँ के नाम' अपील, इस त्यौहार को हरियाली के प्रतीक से आगे बढ़ाकर हरित क्रांति के संकल्प से जोड़ती है।

जब बच्चा अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाता है, तो वह न केवल वृक्षारोपण करता है, बल्कि प्रकृति और संबंधों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है। यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और स्थायी धरोहर छोड़ने जैसा है।

कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत सुकमा जिले में चालानी कार्यवाही, दिया गया जनजागरूकता का संदेश

सुकमा(आरएनएस)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत जिले में तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष चालानी कार्यवाही की गई। इस अभियान के तहत जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (कोटपा सिगरेट एण्ड अदर तम्बाकू प्रोडक्ट एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत कुम्हाररास क्षेत्र में पान ठेले, चाय टपरी और किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में एनटीसीपी नोडल अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक द्वारा इस कार्रवाई का संचालन किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 5 चालान बनाए गए। धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन तथा धारा 06(बी) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं भी तंबाकू सेवन से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराएं, जिससे एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज का निर्माण हो सके।

एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत कलेक्टरेट परिसर में फलदार पौधों का रोपण

0 कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों ने लगाए फलदार पौधे

दंतेवाड़ा, (आरएनएस)। जिला प्रशासन द्वारा आज एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत कलेक्टरेट परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने हाथों से पौधारोपण किया। अभियान के अंतर्गत कलेक्टरेट परिसर में कुल 58 फलदार पौधे लगाए गए, जिनमें अमरूद, आंवला, नींबू, कटहल और काजू जैसे पौधे शामिल हैं। इन पौधों का चयन न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाने बल्कि भविष्य में उनके फलों से लाभान्वित होने की दृष्टि से किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि पर्यावरणीय जागरूकता के साथ-साथ समाज में भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित किया जा सके। यह अभियान जिले में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीटी बजाकर मितानिने चला रही है जन जागरूकता अभियान

दंतेवाड़ा, संवाददाता। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायतों में इन दिनों मितानिने जन जागरूकता अभियान चला रही है। उनके द्वारा 'सीटी' बजाये जाने से ग्रामीण समझ जाते हैं कि कोई जरूरी बात होने वाली है। और दरवाजे खुलने के साथ ही ग्रामीण घर से बाहर आते हैं, और मितानिनें हाथ में झोला, चेहरे पर मुस्कान और स्वास्थ्य का संदेश सेवा का संकल्प लेकर उनसे चर्चा करती है। इस अनोखी मुहिम के तहत जिले की मितानिनों ने अब सूचना पहुंचाने का यह नया तरीका अपनाया है, जिसमें वे गांव में सीटी बजाकर घर-घर जाकर मातृ और शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, मलेरिया, एनीमिया, पोषण और स्वच्छता जैसे जरूरी विषयों पर जागरूक करती हैं। इस प्रकार सीटी की आवाज जैसे ही गांव में गूंजती है, तो बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाएं घरों से बाहर आ जाती हैं। सबको पता होता है। अब कुछ जरूरी जानकारी मिलने वाली है। गांव की एक मितानिन, फूलवती, बताती हैं। पहले लोग आसानी से बात नहीं सुनते थे, लेकिन अब सिटी की आवाज उन्हें खींच लाती है। ग्रामीण खुद पूछने लगते हैं कि क्या जानकारी लाए हो आज? इस पहल को असरदार बनाने के लिए मितानिनों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया

कलेक्टर ने हाथियों की सुरक्षा, हाथी मानव संघर्ष की स्थिति को रोकने के संबंध में ली समीक्षा

जशपुरनगर, कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में वन विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर और डीएफओ श्री शशि कुमार ने अधिकारियों से जिले में हाथी और मानव के बीच उत्पन्न संघर्ष की स्थिति को रोकने, हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सर्पदंश की घटनाओं से बचाव हेतु जागरूकता प्रसार जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने वनक्षेत्रों से गुजरने वाले खंभों में लगे विद्युत लाईन जो निर्धारित ऊंचाई से नीचे झूल रहे हैं उसे ठीक करने निर्देश विद्युत विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया की 100 स्थानों में हाई मास्ट लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वनक्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही सर्पदंश से बचाव के बारे में भी जानकारी दे ताकि सर्पदंश की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि एंटी स्नैक वेनम की उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो में भी पर्याप्त मात्रा में है।

गज संकेत एप्प से हाथियों की गतिविधियों की मिलेगी जानकारी

बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार ने बताया की हाथियों की गतिविधियों का विभिन्न माध्यमों से लगातार निगरानी की जाती है और ग्रामीणों का सतर्क भी किया जाता है। उन्होंने गज संकेत एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस एप के माध्यम से इससे जुड़े लोगों को घर बैठे ही उनके क्षेत्र में हाथियों के विचरण की सूचना और अलर्ट मिल जाता है। इस एप से जुड़े लोगों को मोबाईल पर टेक्सट मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से हाथियों की विचरण की गतिविधियां की सूचना दी जाएगी। इससे वे स्वंय सर्तक भी होंगे और आसपास के ग्रामीणों को भी सूचित कर सर्तक कर सकेगें।

विधायक भावना बोहरा और कांवड़ियों ने दूसरे दिन तय की लम्हनी से वन ग्राम महामाई तक की यात्रा

आज तीसरे दिन होगा पंडरिया विधानसभा में कांवड़ यात्रा का प्रवेश

कवर्धा, लोकशक्ति।

छत्तीसगढ़ वासियों और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा नर्मदा मंदिर अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा सोमवार 21 जुलाई से प्रारंभ हुई। इस दौरान भावना बोहरा के साथ लगभग 300 कांवड़ यात्री भी उनकी इस यात्रा में शामिल हुए और प्रथम दिन अमरकंटक से लम्हनी तक और यात्रा के दूसरे दिन लम्हनी से वन ग्राम महमाई तक उन्होंने यात्रा की। नदी में बाढ़ आने की वजह से उन्हें वन ग्राम महमाई में रात्रि विश्राम हेतु रुकना पड़ा।

बुधवार 23 जुलाई को यात्रा का तीसरा दिन है और भावना बोहरा एवं कांवड़ियों का पंडरिया विधानसभा में प्रवेश होगा। इस दौरान वे खुड़िया से दुल्लापुर के मार्ग से गौरकांपा पहुंचेगी जहाँ रात्रि विश्राम के पश्चात् अगले दिन अपनी आगे की यात्रा के लिए गौरकांपा से मोहतरा के लिए वो प्रस्थान करेंगी। इस दौरान भावना बोहरा और उनके साथ यात्रा में शामिल कांवड़ियों के पंडरिया विधानसभा में आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों एवं भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। सभी उनकी इस पुण्य यात्रा हेतु अभिनंदन करने के लिए उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताते चलें की पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक लगभग 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा की जा रही है और भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक पश्चात यह यात्रा पूर्ण होगी। भावना बोहरा ने बताया कि विगत 4 वर्षों से उनके द्वारा कबीरधाम जिले के कांवड़ यात्रियों के लिए अमरकंटक में उनकी सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष उन्होंने भी उनकी इस यात्रा में सहभागी बनने और छत्तीसगढ़ वासियों तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना के साथ यह कठिन कांवड़ यात्रा कर रही हैं। यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश में एक महिला जनप्रतिनिधि द्वारा इतनी कठिन व लम्बी कांवड़ यात्रा की जा रही है। अमरकंटक के जंगलों एवं प्रकृति के बीच से होकर 23 जुलाई को उनका आगमन पंडरिया विधानसभा में होगा। इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे यह यात्रा करने की शक्ति और हमारे कांवड़ यात्रियों से प्रेरणा मिली है। अमरकंटक से चलकर जंगलों और प्रकृति के मध्य से यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और हमें विश्वास है कि हम यह यात्रा अपने तय समयानुसार पूरा करेंगे। हर दिन एक नई सुबह नई उर्जा और माँ नर्मदा एवं भगवान भोलेनाथ जी के जयघोष के साथ हम शुरू कर रहें हैं और यही जयघोष हमें अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर उर्जा दे रही है। यात्रा के प्रथम दिन माँ नर्मदा और नर्मदेश्वर महादेव जी की पूजा-अर्चना करने के पश्चात हमने यह यात्रा प्रारंभ की थी जिसमें मेरे साथ सैकड़ों कांवड़ यात्री और श्रद्धालुगण सहभागी बनें और कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ निरंतर आगे बढ़ रहें है जिसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश और यहां निवासरत हर व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली बनाए रखने एवं हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन परंपरा एवं धार्मिक आस्था से जोड़ना है। सबके जीवन में सुख-समृद्धि का वास हो,हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो यही हमारी कामना है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)